श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : मैं यह जानना चाहता हूं कि देश में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने सम्बन्धी बिल कब तक लाया जायगा ।

MR. SPEAKER : The Minister need not answer to this. Which Bill will be brought and when, etc., cannot be discussed in the House. These things will be decided in the Business Advisory Committee.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : During the last meeting of the Business Advisory Committee...

MR. SPEAKER : The hon. Member may please resume his seat......

SHRI S. M. BANERJEE : I am not asking any question. I requested you that day that some statement should be made by the Education Minister *suo moto* on the teachers' strike. I request you kindly to ask the Education Minister...

MR. SPEAKER : I have already asked him. The hon. Member knows about it. Now we go the next item.

12.10 hours.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. SPEAKER : Mr. Mrityunjay Prasad.

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । किन्तु बहुत सी बातें ऐसी हैं जो उनके भाषण में नहीं आई हैं । आ भी नहीं सकती थीं क्योंकि समय का अभाव उनके पास था और मुझे भी कहना बहुत कुछ है मगर समय का अभाव मेरे पास भी है । थोड़ी कृपा रखियेगा, दो-चार महत्व की बातें जिसमें मैं कह सकूं ।

सबसे पहली बात आ जाती है देश की सुरक्षा की । अभी भी पाकिस्तान और चाइना हमारे देश के अंगों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं । उन्हें हटाने के लिए क्या प्रयत्न किया जा रहा है, यह बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है । केवल बातें ही बातें चलती हैं । इसके बारे में भी कुछ स्पष्ट होना चाहिए । दूसरी बात यह है कि विदेशों के साथ हमारे संबंध ऐसे होने चाहिए कि जिनसे हमारे ऊपर जब कोई हमला करे तो हम समझ जायं कि कौन हमारा समर्थक है, कौन हमारा मित्र है और किसका भरोसा हम नहीं कर सकते । किन्तु अभी तक जैसा चलता रहा है उसमें बराबर हमको अकेले अपने पैरों पर खड़ा रहना पड़ा है और कोई हमारे साथ नहीं आया है । जो हमारे मित्र कहे जाते हैं उन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे भय लगता है । उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि रूस का जहाजी बेड़ा हिन्द महासागर में बढ़ता जा रहा है और रूस हमारा मित्र है । कुछ दिन पहले चीन भी हमारा मित्र था । उसे हम अपना भाई मानते थे । किन्तु राजनीति में कहीं भी मित्रता का संबंध स्वार्थों से अलग नहीं हो सकता । इसलिए हमें मित्रता का लिहाज छोड़कर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी होगी ।

12.12 hours.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

दूसरी तरफ चाहे छोटा देश हो चाहे बड़े देश हों उनके साथ हमें अपने संबंध ठीक रखने होंगे । अभी तक समझ में नहीं आता है कि क्यों एक तरफ इस्रायल तो दूसरी तरफ पूर्व जर्मनी के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध कायम नहीं हुए हैं जबकि साथ ही साथ अरब लीग को हमने डिप्लोमेटिक स्टेटस दे रखा है, जिसके पास न कोई देश है, न राज्य है, न कोई जमीन है । वह केवल एक संस्था भर ही है ।

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बात है अपने यहां अपनी तैयारी दुरुस्त रखना। कहा तो बराबर जाता है कि हमारी सेना तैयार है। सेना की तैयारी हम बढ़ा रहे हैं। किन्तु जब तक हम दूसरों के ऊपर हथियार के लिए बराबर निर्भर रहेंगे, हमारी कमजोरी बनी रहेगी। साथ ही साथ हम इधर यह देख रहे हैं कि हमारी सीमा पर चीन और पाकिस्तान अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं। बल्कि यों कहिए कि वह हमारे देश में ही अपनी शक्ति बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि उनके अधिकृत क्षेत्रों को हम सीमा क्यों मानें ? वह तो हमारे ही हैं। साथ ही साथ उनकी ओर से तोड़-फोड़ और घुसपैठ की कार्यवाही चलती रही है खासकर चीन के संबंध में मैं कहूंगा कि वह सीधे लड़ने के लिए उत्सुक नहीं है क्योंकि उसकी आवश्यकता वह नहीं देखता है। वह हमारे यहां अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा है और दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी आशंका हमारे मन से दूर नहीं हो रही है कि उसने बहुत हद तक हमारे बीच में अपने चेले बैठा दिए हैं जो अभी आज तक यह भी मानने को तैयार नहीं हैं कि चीन ने 1962 में हमारे ऊपर हमला किया था। इसलिए ऐसी मनोवृत्ति वाले लोगों और राजनीतिक दलों का होना बहुत खतरे की बात लगती है और इससे सावधान होना बहुत आवश्यक है।

पाकिस्तान की कहानी दूसरी है। पाकिस्तान के आदमी हमारे यहां बराबर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। पता नहीं चलता कि हम कहां तक उनकी रोकथाम कर पा रहे हैं। कहने को उनके गुप्तचरों पर हमने काफी कड़ाई की है, परन्तु फिर भी बार-बार पता चलता रहता है कि तोड़-फोड़ की कार्यवाहियां हो रही हैं। इसमें मैं स्पष्ट कहता हूं कि मेरा इशारा किसी खास कौम के लोगों पर नहीं बल्कि सभी पर है, जो कि पैसे के लिए या और किसी चीज के लिए गद्दारी करने को तैयार हो जाते हैं और दुश्मनों के हाथ अपने भेद देने को तैयार हो जाते हैं। इसमें एक और चीज है और वह यह है कि कुछ लोगों का ख्याल ऐसा हो गया है कि वह विदेशियों की मदद इसी तरीके से कर सकते हैं कि अपने यहां की शांति भंग करें, झंझट लगाए रखें, झगड़े लगाए रखें जिससे लोग ऊब उठें और फिर जो एकता 62 में देखने में आई, 65 में देखने में आई, वह न आए। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है और यह सब करने के लिए विदेशों से पैसे आया करते हैं। उन पैसों के बारे में बार-बार हमने पूछा है। मगर कभी भी ठीक पता नहीं चलता कि कहां तक उसका पता आप लगा सके हैं या लगाने की कोशिश कर रहे हैं ? जैसे कि कहा जाता है, मन में शंका है, सबूत तो मेरे पास नहीं हैं कि पिछले चुनाव में भी विदेशों से पैसे आए और कोई जरूरी नहीं कि चुनाव के महीने बीस दिन पहले ही आये हों, बल्कि पहले से उनका इंतजाम होता रहा है और उसके लिए कई जरिये रहे हैं जिनमें दो एक की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ऐसी आशंका है, मेरे पास प्रमाण नहीं हैं, यह मैं स्पष्ट कहे देता हूं, जैसे कि आप कुछ देशों के साथ जब विदेशी मुद्रा के स्थान पर भारतीय मुद्रा रुपये में व्यापार करते हैं, बार्टर, अदला-बदली में व्यापार करते हैं, वहां देखने में आता है कि आप घाटे का सौदा करते हैं न कि मुनाफे का। आप उनको तो सस्ता माल देते हैं चूंकि आपको एक्सपोर्ट करना है, बेचना है और उनसे माल आप रुपये में लेते हैं, इसलिए बहुत खुश हैं, मगर ऐसा भी देखने में आता है, इसके बहुत नमूने हमारे सामने आए हैं कि जहां दूसरे देशों से सस्ता माल मिलता है या मिल सकता है, वहां उसके बदले रुपये या अदला-बदली का व्यापार करने वाले देशों से हमने महंगा लिया या अगर वाजिब कीमत में लिया तो

उस माल की क्वालिटी बहुत घटिया रही और हम कुल मिलाकर घाटे में ही रहे। ऐसे व्यापार में जो लोग बीच में पड़े हुए हैं वह अपने कमीशन के जरिए और किस-किसके जरिये क्या-क्या करते हैं यह आपके देखने की बात है। मैं कहता नहीं हूं कि ऐसा होता है किन्तु यह शंका की बात है।

अब हम घर की तरफ आएं। हमारे यहां इस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है केन्द्र और राज्य का संबंध। उसमें एक बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि कुछ लोग ऐसी सरकार बनाने को उत्सुक हैं कि अपने हाथ में शक्ति लेकर केन्द्रीय सरकार से झगड़ा करें, केन्द्र को हमेशा गलत जगह पर रख दें जिससे यहां की सरकार की शिकायत हो, वह बदनाम हो, केन्द्र की बदनामी हो। और यह जो करते हैं उनके साथ तो यह मुश्किल हो जाती है कि वही भेड़िया वाली कहावत याद आती है कि तू नहीं तो तेरे बाप ने पानी जूठा किया होगा। यानी कुछ भी हो, किसी तरह से भी हो, जब उन्हें झगड़ा ही करना है, कोई न कोई झंझट ही खड़ा करना है तो उसके लिए किसी बहाने की दरकार नहीं है, हमेशा बहाने मौजूद हैं और इसका हर बार जवाब देते जाना, रोक-थाम करना, कोई रास्ता निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आखिर सभी जगह समझदार आदमी भी हैं जो इन बातों को समझते भी हैं। उन लोगों से मिलना होगा और बार-बार हर बात पर केन्द्रीय सरकार को इसका प्रचार भी करते जाना होगा कि ऐसे राज्य क्या मांगते हैं, क्या उन्हें दिया जाता है और क्यों उनकी शिकायत होती है, शिकायतों में क्या तथ्य है। अगर शिकायतों में तथ्य है तो उसे दूर करना होगा और इसका ध्यान रखना होगा जिसमें वाजिब, सही शिकायतें न रहने पायें।

दूसरी तरफ एक चीज अभी हुई है, आज कल के अखबारों से मालूम हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है और उससे थोड़ी चिन्ता हो गई है। इसलिए नहीं कि केरल में आपने एक नया जिला बनाया है। आप जिले बहुत से बना सकते हैं प्रशासनिक दृष्टि से। उसमें कोई झगड़ा नहीं है। परन्तु उसके भीतर कारण क्या है, किस लिए बनाया गया है, यही चिन्ता की बात हो जाती है। अगर जिस बात के लिए मांग की गई उसी बात के लिए वहां नया जिला बनाया गया है तो फिर आगे के लिए क्या हम अपनी अखंडता संभाल सकेंगे? हमें अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए सिर्फ शक्ति ही नहीं चाहिए, मनोबल भी चाहिए। लोगों को समझाना चाहिए और साथ ही साथ नई पीढ़ी के लोगों के दिलों में देश की, स्वदेश की भावना जगानी चाहिए। इसके विपरीत अगर हम केवल किसी वर्ग विशेष को प्रसन्न करने, राजी रखने के लिये इस तरह से राज्यों के टुकड़े करें तो वह एक शिकायत की बात हो जाती है और उससे चिन्ता पैदा होती है। किन्तु यदि आप प्रशासनिक दृष्टि से करें तो आप चाहे पचास जिले बनायें, उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है, क्योंकि यह तो प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी हो जाता है।

अब मैं शिक्षित बेरोजगारों के सवाल को लेता हूं। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई मेरी समझ में पहली तो यह है कि पढ़े-लिखे लोगों को इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि उनके लिये रोजगार ढूंढना मुश्किल हो रहा है। इन्जीनियर बनाये जा रहे हैं, जो व्यावहारिक काम में इतने अच्छे नहीं हैं, जितनी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। क्योंकि 18 वर्ष की उम्र के लड़के तकनीकी कालेजों में लिये जाते हैं और वहां उनके हाथ-पांव उस काबिल नहीं रहते कि वे इतनी मेहनत कर सकें जितनी मेहनत कि इन्जीनियर को करनी चाहिये। दूसरी तरफ थ्योरेटिकल साइड, पुस्तकीय, वैज्ञानिक पहलू में उनके पास दूसरे सम्बद्ध विषयों का ज्ञान उतना

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

नहीं होता कि वे थ्योरेटिकल साइड में भी अच्छे बन सकें। दूसरी कठिनाई यह है कि जब तक औद्योगिक विकास नहीं होगा, इन लोगों को रोज़ी कहां से मिलेगी। औद्योगिक विकास में एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आती है कि हमारे यहां काम करने वालों को यह नहीं सिखाया जाता कि तुम अपने हक के लिये लड़ो, जरूर लड़ो, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्शन को बढ़ाना कायम रखना भी हमारा कर्तव्य हैं। देश के लिये तुमको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, इसमें घड़ी-घण्टे का हिसाब थोड़ा कम होना चाहिये। अपनी ड्यूटी पूरी रहे—उस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आज मुश्किल यह है कि हर तरफ गो-स्लो से काम करने की भावना चल रही है और श्रम कानून में गो-स्लो शब्द ही नहीं है। इस सम्बन्ध में दूसरी जो बाधाएं हैं, उन की डिटेल में, मैं इस समय नहीं जाना चाहता, जैसे घेराव होता है, इसको मैं यहीं छोड़ देता हूं।

जहां तक अशिक्षित बेरोज़गारों का सम्बन्ध है, इसके बारे में एक बहुत बड़ी शिकायत है, खासकर ऐसे उपक्रमों में जहां सरकार का हाथ है। यह सही बात है कि सारा देश एक है और सब जगह काम करने का अधिकार है और सब जगह काम करने की सुविधा मिलनी चाहिये, किन्तु यह भी सत्य है कि जैसे दिल्ली में कोई काम होगा, तो दिल्ली के आस-पास वालों को उसमें काम करने की ज्यादा सुविधा होगी। मैं यह उदाहरण इसलिये दे रहा हूं कि बिहार में इस चीज की शिकायत बहुत ज्यादा हो रही है कि वहां के सरकारी उपक्रमों में दूर-दूर से लोगों को बुलाया जाता है, यहां तक कि माली, दरबान, आदि पदों के लिये भी हज़ार मील या डेढ़ हजार मील दूर से लोगों को लाया गया है। मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार हूँ कि 10-20 वर्ष पहले बिहार में इन्जीनियरों की कमी थी, इसलिये उनको बाहर से लाया गया, लेकिन अब तो इन्जीनियरों की भी कमी नहीं है। अगर अब आप यह कहें कि माली या मजदूर बिहार में नहीं मिलते हैं, इसलिये डेढ़ हजार मील दूर से उन्हें लाया गया है, यों यह बातें बहुत कड़वी लगती हैं। सिद्धान्ततः चाहे जो बात हो, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से यह ठीक नहीं है, नतीजा यह हो रहा है कि शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों के नवयुवकों में बहुत ज्यादा क्षोभ पैदा हो रहा है। इसी फ्रस्ट्रेशन की निशानी शिव सेना है, लचित सेना है और इस तरह की और भी बहुत सी सेनाएं बनी हैं। मैं यह मानता हूं कि इन सेनाओं के पीछे और भी बातें होंगी, लेकिन आर्थिक कठिनाइयां न हों, तो इनको इतना बल नहीं मिलेगा।

अशिक्षित लेबर के प्रश्न पर मैं महीनों से लड़ रहा हूं, लेकिन मुझे अभी सरकार से स्पष्ट जवाव नहीं मिला है। यहां पार्लियामेन्ट में पिछले दिसम्बर महीने में स्वीकार किया गया था कि उत्तर बिहार में मिट्टी की कटाई के लिये 7 रुपये रोज पर मज़दूरों को बाहर से बुलाया गया था जबकि वहां स्थानीय मज़दूर 3 रुपये रोज पर उपलब्ध थे। इस प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार से या बिहार सरकार से कहीं से भी मुझे सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। राज्यपाल के सलाहकार से मैंने पूछा तो मुझे यह कहा गया कि इस प्रश्न पर हमने गवर्नमेन्ट आफ़ इण्डिया को खत भेज दिया है, लेकिन मेरे सामने अभी तक वह उत्तर नहीं आया—

MR. DEPUTY-SPEAKER : Is it Rs. 7/- per day ?

श्री मृत्युंजय प्रसाद : जी हां, इस चीज़ को यहां स्वीकार किया गया है। बाबू सिद्धेश्वर प्रसाद उपमन्त्री ने स्वीकार किया है। मैंने उस प्रश्न की आफिशियल कापी बिहार गवर्नमेन्ट के एडवाइजर श्री एम. एस. राव को चव्हाण साहब के सामने दी थी। इससे अधिक मैं क्या कर सकता था। अगर

इसी तरह से काम होता रहा तो इस तरह की सेनाओं को आप कैसे रोक सकेंगे, ये बातें होकर रहेंगी।

हमारे यहां सुरक्षा और विकास के लिये, खास कर इकानामिक विकास के लिये आवश्यक है कि एटामिक रिसर्च स्टेशन या एटामिक पावर स्टेशन बनाया जाना चाहिये। आप जानते हैं कि बिहार में यूरेनियम माइन्ज़ पायी गयी हैं और उनसे यूरेनियम निकाला जा रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है कि बिहार में भी उसका समुचित उपयोग किया जा सके। अखबारों में ऐसी सूचनायें निकली हैं कि इस तरह की रेअर-अर्थ्स या रेअर-मिनरल्ज़ विदेशों को भेजी जा रही हैं और ऐसी भी आशंका की जा रही है कि ये चीजें दूसरे रास्ते से हमारे दुश्मनों के हाथों में पहुंच रही हैं। इसमें कितना सत्य है, इसका पता लगाना सरकार का काम है, मैं तो अखबारों में पढ़ी हुई बातों की ओर ही आपका ध्यान दिला सकता हूं।

एक और विषय की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—है तो यह परिहास की बात, परन्तु परिहास की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं। थोड़ी देर के लिये मान लीजिये कि किसी राजा साहब से मेरी बातें हुईं, जो बहुत परेशान हैं, इसलिये कि प्रीवीपर्स खत्म हो जायगा तो वे क्या करेंगे। उन्होंने एक व्यापार शुरू किया। मैंने पूछा कि किस चीज़ का व्यापार शुरू किया है। उन्होंने कहा कि जवाहरात का व्यापार शुरू किया है...

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय) : राजा लोग क्या चिनिया-बदाम का व्यापार करेंगे ?

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैंने पूछा कि कहां से मंगाते हैं, कहां भेजते हैं, क्या मुनाफा हो रहा है। बोले—बिक्री तो काफ़ी अच्छी है। अभी मंगाने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि बाप-दादाओं की जो जमा है, अभी वही बेच रहे हैं, लेकिन घाटा बहुत लग रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन और दुकान चलाने में तथा सेल्ज़-मैन को कमीशन देने में ही सारा दाम निकल जाता है, बल्कि घर से भी कुछ देना पड़ता है, फिर भी हम व्यापार कर रहे हैं। इस काम में राजा साहब की कितनी तारीफ़ की जायगी, आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसी ही तारीफ़ हमारे यहां की कुछ संस्थाओं की हो रही है। अभी तीन दिन पहले, ता० 18 फरवरी को एन.एम. डी. सी. के बारे में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मुझे यह जवाब मिला कि जापान को जो आयरन-ओर भेजा जा रहा है उसमें 2 करोड़ 95 लाख रुपये का घाटा हुआ है। इस काम में आपको कुछ बनाना नहीं था, लाखों-करोड़ों वर्षों से परमात्मा ने यह खनिज पदार्थ पृथ्वी में भर दिया है, उसको निकाल कर आपको भेजना था, लेकिन उसमें भी आप कुबूल करते हैं कि 2 करोड़ 95 लाख रुपये का घाटा हुआ।

इसमें भी आप खुश हैं और कहते हैं कि आपको रेल-भाड़े में कुछ पैसे मिल गये हैं, हैण्डलिंग चार्जेज टु दी पोर्ट में 2 करोड़ 31 लाख रुपया मिला है, 1 करोड़ 25 लाख रुपया एक्सपोर्ट ड्यूटी का मिला है, 40 लाख रुपया रायल्टी का मिला और 14 लाख रुपया एम. एम. टी. सी. की कमीशन का मिला है, किन्तु इस सबके बावजूद भी आपको 2 करोड़ 95 लाख का घाटा हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि आप घर के जवाहरात को बेच रहे हैं फिर भी आपका खर्च पूरा नहीं होता, उसके बावजूद भी आप जापान के साथ और दूसरे देशों के साथ यह सौदा करते जा रहे हैं और करते जायेंगे। अभी दो तीन दिन पहले, 18 तारीख को मुझे अनस्टार्ड क्वेश्चन का जवाब मिला है। अब मैं क्या कहूं ? अगर इसी तरह से आपको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट से पैसा पैदा करना है तो फिर अच्छा यही होगा

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]
कि आप एक्सपोर्ट न करें। किसी तरह दुख-सुख से काम चल ही जायेगा लेकिन यह तरीका तो किसी तरह से भी जंचता नहीं है।

दूसरी तरफ जहां तक पब्लिक अन्डर-टेकिंग्ज़ का सम्बन्ध है, सब में तो नहीं, लेकिन बहुतों में घाटा चल रहा है। उनके सम्बन्ध में बातें होती हैं, कमेटीज़ विचार करती हैं लेकिन क्या नतीजा निकलता है, यह मालूम नहीं। मैं अपनी ओर से तीन-चार बातों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरा खयाल है कि अगर उन पर ध्यान दिया जायेगा तो कुछ हद तक शायद उनका घाटा कम हो सकेगा। एक बात तो यह है कि उनके जो अफसर बनाये जाते हैं उनके बारे में इस बात का विचार कम रखा जाता है कि जिस काम के लिए उनको भेजा जा रहा है, उस काम में उनकी योग्यता कहां तक है। दूसरी बात यह है कि इस बात को मान लेना कि जो अफसर प्रशासन में बहुत सफल है वह इन संस्थाओं को लाभपूर्वक चलाने में भी सफल होगा, यह आवश्यक नहीं है। इसमें एक्सेप्शन्स, अपवाद हो सकते हैं। बहुत से आई० सी० एस० आफिसर्स, हो सकता है कि दोनों स्थानों पर सफल सिद्ध हों। यह भी सम्भव है कि जो अफसर प्रशासन में असफल हों वे इन संस्थाओं में सफल सिद्ध हों। इसलिए जो लोग ऐसी संस्थायें सफलता से चला सकने की योग्यता रखते हों, चाहे वे सरकारी अफसर हों, या न हों, उन्हें ही आप इन संस्थाओं में बिठाइये। इसके साथ ही पब्लिक से भी कुछ लोगों को इन संस्थाओं में रखा जाता है। ऐसे लोगों को ले रहे हैं, जिनका उस अमुक व्यापार से या संस्था से, पहले से कोई विशेष सम्बन्ध था, इसका पता नहीं चलता है। वे लोग वहां जाकर जो कुछ करते हैं, मैं उसकी शिकायत नहीं करता, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कोई भी यूनिफार्म कोड आफ रेक्रूटमेन्ट ऐन्ड प्रमोशन आज तक नहीं बना है। उदाहरण-स्वरूप मैं एक बात कहूंगा। चार पांच साल पहले की बात है। इंडियन आयल के चेयर-मैन जब जाने लगे तो उन्होंने बहुतों को 5-6 इंक्रीमेन्ट्स दे दिए, किसी-किसी को तीन-चार इंक्रीमेन्ट्स दे दिये। यानी जैसा दिल में आया वैसा कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं था। क्योंकि सारी शक्ति आपने उनको दे रखी थी, तभी जबकि उनको आपने रखा था। वे इस्तीफा भी दे चुके थे, उस के बाद भी आपने उनको रखा। अब सवाल यह है कि जो इस्तीफा दे चुका हो उसको फिर फरदर इन्टेरेस्ट क्या रह जायेगा, जो भी वह चाहेगा, वही करेगा।

एक बात यह भी है कि सरकारी उपक्रमों के अधिकारियों को सरकार ऐसे अधिकार नहीं देती है कि वे समय पर उचित निर्णय ले सकें और अपने काम को ठीक से चला सकें, जबकि दूसरी तरफ उनको जरूरत से ज्यादा अधिकार दे दिये जाते हैं। प्रशासन से सम्बन्धित अधिकार देते हैं लेकिन उस व्यापार से सम्बन्धित अधिकार नहीं देते हैं। तीसरी बात यह है कि जब कोई काम शुरू किया जाता है तब उसके प्रारूप में अगर सौ करोड़ के इन्वेस्टमेन्ट की बात कही जाती है तो उस काम के पूरा होते-होते तीन सौ या चार सौ करोड़ तक की पूंजी लग जाती है। इस तरह से शुरू का सारा हिसाब-किताब गलत हो जाता है। अब अगर आप अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी करें तब भी जो लाभ होगा वह अपेक्षित लाभ का 1/4 ही रह जायेगा। इस तरह से इसमें लाचारी आ जाती है और कोई उपाय नहीं रह जाता है।

इसके अलावा एक बात यह है कि आप इस बात का खयाल ही नहीं रखते कि जो चीज बनाई जायेगी उसकी बिक्री भी होगी या नहीं या किस रूप में होगी। इसके लिए जरूरी है कि जो लोग उसके चार्ज में हैं वे यह देखें और इस सम्बन्ध में सरकारी और दूसरी

संस्थाओं से बात-चीत करके पता लगायें कि उनको कौन सा और कैसा सामान चाहिए। हैवी इंजीनियरिंग की तो यह स्थिति है कि उसको बड़ा काम चाहिए और ऐसे बड़ी मशीनों के आर्डर को पूरा करने में कई वर्ष लग जायेंगे, इसमें उसका कोई दोष भी नहीं है। कई वर्ष आगे के आडर्स उसे मिलने चाहिए। लेकिन इसके लिए जो-जो पार्टीज़ हों उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या-क्या चाहिए। परन्तु ऐसा किया नहीं जाता है। दूसरी तरफ चीज़ यह है कि जिनके पास आदमी दौड़ कर जायेंगे और पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, उनको इस बात की फिक्र थोड़ी ही रहती है कि हमें यह आर्डर गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की संस्था को देना है बल्कि उन्हें इस बात की फिक्र रहती है कि हमारा अपना फायदा किस बात में है। आज जो घाटा हम जापान के साथ व्यापार में उठा चुके हैं यदि वह यहीं हमारे उपक्रमों के पारस्परिक व्यापार में आपस में ही रह जाता तो बहुत कुछ काम हो जाता लेकिन इस बात को सोचा नहीं जाता है।

अब मैं आपका ध्यान एक बहुत जरूरी बात की तरफ दिलाना चाहूंगा। हमारे यहां टूरिज्म का विकास करने की बहुत कोशिश हो रही है। वह वाजिब बात है, होनी ही चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि यात्रा-स्थल विशेषकर दो दृष्टियों से प्रसिद्ध किए जा रहे हैं। एक तो प्राकृतिक सौंदर्य और दूसरे प्राचीन महलात खंडहर मकानात वाले इत्यादि। हम टूरिज्म के सम्बन्ध में विदेशियों का ज्यादा ध्यान रखते हैं, उसी में अपना अधिक लाभ समझते हैं, परन्तु हमारे यहां अपने देश में भी यात्रा करना एक बहुत बड़ी बात रही है। हमारे देश के यात्री कन्याकुमारी से लेकर बद्रीनाथ तक बराबर आया-जाया करते हैं, परन्तु इस बात को हम भूलते जा रहे हैं। इसमें कोई धार्मिक भावना की बात नहीं है बल्कि हमें राष्ट्रीय भावना को देखना है ताकि हमारे बच्चे उससे प्रेरणा लें और वहां परजायें। उदाहरण के रूप में मैं चितौड़ के किले का नाम ले रहा हूं। आज वह किला टूटता जा रहा है। कई साल पहले राजस्थान के मुख्य मन्त्री स्वर्गीय श्री माणिक लाल वर्मा ने महाराणा उदयपुर से उसे लिया था और गवर्नमेन्ट आफ इंडिया को उसे दिया, लेकिन हुआ यह कि उसकी मरम्मत नहीं हो रही है और वह टूटता जा रहा है। भारत के इतिहास में चितौड़ का क्या स्थान है, यह उसी को बतलाना होगा जोकि कुछ भी न जानता हो। उसके भीतर का मीरा का मंदिर टूटता जा रहा है। सामान सब-कुछ है लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हो रही है, मकानात टूटते जा रहे हैं। वहां पर सवारियों की भी कोई व्यवस्था नहीं है और न ही रात में किले में जाकर ठहरने की कोई व्यवस्था है। इसी तरह से हल्दीघाटी में जायेंगे तो वहां भी कोई खास चीज़ देखने की नहीं बची है। उसको भी बनाना बहुत जरूरी है। वहां पर जो प्रेरणा मिलती है वह खेम-करण के युद्ध में हमारे काम आई है। इसी तरह से बिहार में शेरशाह और पिछली शताब्दी के कुंवरसिंह के लिए आपने क्या किया? उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। वहां पर भी दर्शनीय स्थान मौजूद हैं जोकि बड़े सुन्दर भी हैं और उनका महत्व भी बहुत है।

डा० राम सुभग सिंह जब रेलवे में राज्य मन्त्री थे तब उन्होंने भी वायदा किया था सन् 66 में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, कि एक ऐसी लाइन का निर्माण किया जायेगा जिसमें कोटा, चितौड़ इत्यादि सभी आजायेगा। उस समय कोटा-चितौड़ लाइन की मंजूरी दे दी गई थी। संयोग से वे यहां बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपने पुराने वायदे को ध्यान में रखें। अब कहा जाता है कि वह घाटे की लाइन है। लेकिन साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेन्स की लाइन भी है और जैसे-जैसे कृषि की उन्नति होती

[श्री मृत्युंजय प्रसाद]

जा रही है, वह क्षेत्र आगे बढ़ता जा रहा है और आगे चलकर वह घाटे की लाइन नहीं रह जायेगी । एक बात और है, क्षमा कीजियेगा, जरा कडुई लगेगी । आप यह बड़ा सुन्दर काम कर रहे हैं कि बौद्ध तीर्थों को प्राथमिकता दे रहे हैं क्योंकि वहां पर विदेशों से यात्री आयेंगे । लेकिन साथ ही साथ इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि आप गैर बौद्ध तीर्थों की उपेक्षा करें । उनके ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है । कुछ नहीं तो उनको नष्ट होने से बचाना है उनको सँभालना है । मैं इसमें किसी एक जाति का नाम नहीं लेता किन्तु उदाहरण के लिए मैं जैनियों का नाम भी लूंगा । मुझे कहना तो बहुत-कुछ था लेकिन समय के अभाव में मुझे बैठना पड़ रहा है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने आर्थिक उन्नति का बहुत ढिंढोरा पीटा है । इस अभिभाषण में भी उसकी बहुत चर्चा है । मैं जानना चाहता हूं कि वह क्या उन्नति है ? कहा गया है कि खेती में हमारी इतनी उन्नति हुई है, इतनी उपज बढ़ी है इसलिये बढ़ी है कि पिछले साल वर्षा अच्छी हो गई । जब वर्षा अच्छी हो जाय और उसके कारण खेती अच्छी हो जाय तो उसका श्रेय कांग्रेस को और यदि वर्षा न हो, इन्द्र देवता नाराज हो जायें तो फिर कहते हैं कि हम क्या करें । "मीठा-मीठा हप्प और कडुवा-कडुवा थूं" की यह नीति नहीं चलेगी । अगर आपने खेती के लिये कुछ किया होता तो आज राजस्थान के अन्दर अकाल की स्थिति न होती ।

आज वास्तव में इस सरकार के ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह है कि इसने 22 वर्षों के राज्य-काल में खेती की उपेक्षा की है । हमारे देश की बुनियादी इंडस्ट्री खेती है, देश की खुशहाली का आधार खेती है । अगर किसान के पास पैसा होता है तो वह बाजार से माल खरीदता है । वह साइकिल खरीदता है, रेडियो खरीदता है, फलस्वरूप व्यापार बढ़ता है और फैक्ट्री भी चलती हैं । और जब किसान की जेब में पैसा नहीं होगा तो न व्यापार चलेगा और न फैक्ट्रियां चलेंगी । जब दो साल वर्षा नहीं हुई, खेती चौपट हो गई और सारे देश में रिसेशन हो गया । गत वर्ष वर्षा अच्छी हो गयी उसका क्रैडिट यह ले रहे हैं । मेरा कहना है कि आज भी सरकार खेती की ओर जो ध्यान देना चाहिये वह नहीं दे रही है ।

चौथी योजना देखिये । 14,500 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर के उद्योगों आदि के लिये रखा है और खेती के लिये 3000 करोड़ भी नहीं है । इससे साफ ज़ाहिर है कि खेती की ओर ध्यान नहीं दिया गया है और आज भी नहीं दिया जा रहा है । अगर खेती की ओर ध्यान दें —अगर हम अपने हर खेत को पानी देने का प्रबन्ध करें, और वह हम कर सकते हैं, तो हमारे देश के अन्दर किसान खुशहाल होगा और परिणामस्वरूप सारा देश समृद्ध होगा । इसलिये आज सरकार का यह दावा करना कि उसने खेती की ओर ध्यान दिया है और उसके कारण उपज बढ़ी है ठीक नहीं है । इसका क्रैडिट सरकार को नहीं जाता, बल्कि इसका श्रेय इन्द्र देवता या किसान को है जिसने अपनी मेहनत से पैदावार बढ़ाई है ।

जहां तक उद्योगों का ताल्लुक है, उन्नति की हालत यह है कि जो सरकारी उद्योग हैं और जिनके लिये करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं वे उद्योग घाटे में चल रहे हैं । अभी तक हमारा इनवेस्टमेंट जो सरकारी उद्योगों पर है वह 3,000 करोड़ से अधिक है । अगर 10 परसेंट का विनिमय प्रौफ़िट लगाया जाय तो हर साल 300 करोड़ की आमदनी होनी चाहिये जिससे हम अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ा सकते हैं तथा देश में उन्नति के

और काम कर सकते हैं। मगर बजाय 300 करोड़ आमदनी होने के हर साल 40, 50 करोड़ का घाटा हो रहा है। कोई और संस्थान बताइये जहां इतना इनवेस्टमेंट करने पर भी यह हालत हो। लेकिन सरकारी उद्योगों की हालत अजीब है। आप यह भी नहीं कह सकते कि सरकारी उद्योगों के कर्मचारियों को आप बेहतर पे देते हैं, या उनको रहने का बेहतर स्थान देते हैं। फिर भी घाटा होता है और देश का नुकसान करते हैं। कारण क्या है ? कारण यह है कि आप की औद्योगिक नीति गलत है और जो रुपया आपके पास है उसको भी आवश्यक काम के लिये खर्च नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बोकारो के लिये 600 करोड़ रुपया रख रहे हैं और दूसरी ओर राजस्थान कैनाल को पूरा करने के लिये आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। एक तरफ महाराष्ट्र के अन्दर आप नई शुगर मिलें खोल रहे हैं और दूसरी तरफ यू० पी० और बिहार के अन्दर मिलें बन्द हो रही हैं, या जो उनकी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी है उस पर पूरी तौर पर काम नहीं कर रही हैं। यह कोई औद्योगिक नीति नहीं है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि हमारी औद्योगिक नीति सफल हुई है।

कहा गया है कि हम सिंचाई के लिए एक सिंचाई कमीशन बनायेंगे। अच्छी बात है। मगर सिंचाई की क्या हालत है हमारे देश के अन्दर यह भी तो देखिये। जिस समय हमारे देश में पौंग डैम का काम शुरू हुआ था उसी समय पाकिस्तान में मंगला डैम शुरू किया गया। पाकिस्तान ने मंगला डैम पूरा कर लिया, वहां उससे सिंचाई हो रही है और हमारे यहां पौंग डैम का काम आधा भी नहीं हुआ है। राजस्थान कैनाल शुरू हुए कितने वर्ष हो गये हैं। परन्तु अभी भी वह बनी नहीं। हमारे पास कोई सैंस आफ़ प्रायरिटी नहीं है। प्रधान मंत्री के मकान के लिये 50 लाख रुपये निकल सकते हैं मगर जो देश के उद्योग के लिये, देश के किसान और मजदूर के लिये रुपया चाहिये उसके लिये कहते हैं कि रुपया नहीं है। यह कोई उद्योग नीति नहीं है। यह एक खिलवाड़ किया जा रहा है।

राष्ट्रपति के भाषण में कहा गया है कि हमारी विदेश नीति बड़ी सफल रही है, हमने नये साथी बनाये हैं, मित्र बनाये हैं। मैं हैरान हूं कि यह क्या विदेश नीति है ? जिन नारों पर यह विदेश नीति 1947 में बनी थी वही नारे आज भी चल रहे हैं जब कि संसार की परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। पिछले एक साल के अन्दर हमारे इर्द-गिर्द के देशों के अन्दर एक बहुत बड़ा चेन्ज आया है। कल तक रूस को हम अपना मित्र मानते थे, आज उसकी नीति में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। वह पाकिस्तान के ज्यादा निकट जा रहा है। मिडिल ईस्ट के अन्दर वह यू० एस० ए० और यू० के० का स्थान ले रहा है। आज सारे अरब देश और पाकिस्तान इसके चंगुल में हैं। रूस की नीति में बदल क्यों आया ? जाहिर है कि हर देश अपनी परिस्थितियों और हितों को देखकर अपनी विदेश नीति बनाता है और इसके लिये दुनिया का कोई भी मुल्क किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता। पाकिस्तान को चीन से हथियार मिले, और अब उसे रूस से भी हथियार मिल रहे हैं, और परिणाम यह हुआ कि ये अरब देश, जिन के पीछे हम भागते रहे हैं, आज पाकिस्तान के निकट आ रहे हैं। वह पाकिस्तान को मानो एक अरब देश मानने लगे हैं। उन सबका एक गुट बन गया है। जिस प्रकार यू० के० कभी मिडिल ईस्ट के अन्दर मुस्लिम भावना को जगा कर वहांके तेल का लाभ उठाना चाहता था उसी प्रकार आज रूस इस इलाके की मुस्लिम भावना को जगा कर वहां के तेल और अन्य साधनों का फ़ायदा उठाना चाहता है। उस की नीति परिवर्तन के कारण हमारे देश पर पड़ा है। आज अरब हम से दूर जा रहे हैं, पाकिस्तान पहले ही दूर था। मगर हमारी

[श्री बलराज मधोक]

नीति वही चल रही है। हमने विचार नहीं किया कि यह जो बदल आया है परिस्थिति के अन्दर उसके अनुसार हम भी अपनी नीति बदलें।

आज वैस्ट एशिया की स्थिति यह मांग करती है कि जो देश इस नीति के बिरुद्ध हैं और जो अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं उन के साथ हम मित्रता का व्यवहार बढ़ायें। आज इज़राइल, जिसने सारे अरबों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उसने यह सिद्ध कर दिया है कि उसे भी रहने का अधिकार है संसार में, संसार के अन्दर सरवाइवल आफ़ दी फ़िटेस्ट का जो पहले नियम था, वही आज भी है। जो हमारा मित्र देश है, जो हम को सहायता भी दे सकता है उसे आज हम गालियां देते हैं। ईराक में बेगुनाहों की हत्या होती है, हमारी ज़बान पर ताला लग जाता है। मगर वहां कुछ भी होता है तो हम बोलने लगते हैं। यह क्या नीति है? हमें पश्चिम एशिया के बारे में अपनी विदेश नीति के अन्दर मूलभूत परिवर्तन करना चाहिये। मैं नहीं कहता कि अरबों से बिगाड़ करो, मगर यह जरूर कहता हूं कि इज़राइल से दोस्ती करो। ईरान के शहनशाह हमारे यहां आये थे, आज इज़राइल के साथ उनके सम्बन्ध बहुत अच्छे हैं। अगर ईरान एक मुस्लिम देश होते हुए भी इज़राइल के साथ बड़े निकट सम्बन्ध रख सकता है तो नासिर मियां हमें कहने वाले कौन हैं कि क्योंकि तुम हमारे मित्र हो इसलिये इज़राइल के मित्र नहीं बन सकते? अगर नासिर साहब कह सकते हैं कि वह भारत के साथ-साथ पाकिस्तान और चीन के भी दोस्त हैं तो हम उनसे क्यों नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे भी दोस्त हैं और इज़राइल के भी दोस्त हैं? पश्चिम एशिया में रूस की बदलती हुई नीति के अनुसार आप को भी अपनी नीति बदलनी होगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मार खायेंगे।

पाकिस्तान की शक्ति बढ़ रही है और पाकिस्तान के अन्दर जो हालात पैदा हो रहे हैं वे हमारे लिये भी खतरनाक हैं। आज पाकिस्तान के अन्दर वार आफ़ सक्सेशन चल रहा है, उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है। यह डैमोक्रेसी की लड़ाई नहीं है। मुस्लिम देशों के अन्दर ऐसा होता रहता है। अपने देश के अन्दर जो असंतोष है उससे जनता का ध्यान हटाने के लिये वहां का तानाशाह कभी भी अपनी सेना का मुंह भारत की ओर मोड़ सकता है। यह पाकिस्तान की अन्दर की हालत हमारे लिये खतरे की घंटी है। चीन और पाकिस्तान का गठबन्धन है इसलिये वहां जो भी होता है, जो हालात होते हैं, उन पर चिन्ता करने की जरूरत है, और अपनी शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। अपनी विदेश नीति के अन्दर उचित परिवर्तन लाने की जरूरत है। वह हम नहीं कर रहे हैं।

पूर्व एशिया के अन्दर एक वैकुअम पैदा हो रहा है। यू० के० वहां से विद्ड्रा कर रहा है, यू० एस० ए० वहां से विद्ड्रा कर रहा है। इंडियन ओवेशन से भी वे पीछे हट रहे हैं। एक खला पैदा हो रहा है। हमारी प्रधान मंत्री कहती हैं कि मैं इस वैकुअम के सिद्धान्त में विश्वास नहीं करती। मुझे प्रधान मंत्री की इस बात पर गुस्सा नहीं आता बल्कि उन पर दया आती है। जितनी उनके अकल है उसके मुताबिक ही तो वह बात करेंगी। इन्टरनेशनल जगत में पावर वैकुअम की स्थिति पैदा होती है। अभी पिछले दिनों जब मैं दक्षिण विएटनाम गया था और वहां के प्रधान मंत्री से मैंने पूछा कि उनकी समस्या क्या है तो वह कहने लगे कि हमारी समस्या बड़ी सिम्पल है।

"My country is the meeting ground of India and China. Culturally we are near

India; geographically we are near China. With the withdrawal of the French there is a power vacuum in Vietnam. China is trying to fill that power vacuum; we are trying to resist it. America is helping us but America cannot fill this vacuum. This vacuum has to be filled either by China or India but unfortunately, India is nowhere in the picture; so, we are forced to fall into the Chinese lap."

विएटनाम के प्रधान मंत्री ने बताया कि वहां एक वैकुअम पैदा हो चुका है। अब अगर हम उस वैकुअम को नहीं भरेंगे तो चीन भरेगा या और कोई भरेगा। वैकुअम रह नहीं सकता है। आज हम अकेले उस वैकुअम को नहीं भर सकते इसलिये आवश्यक है कि हम रीजनल गठजोड़ करें, चाहे इंडोनेशिया हो, जापान हो, आस्ट्रेलिया हो या थाईलैंड हो। इन मुल्कों से मिल कर चलना चाहिए। हमें आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में और सैनिक मामलों में इनसे तालमेल बढ़ाना चाहिए तभी जाकर यह जो वैकुअम पैदा हो रहा है उस को हम फिल कर सकेंगे और चीन व रूस को उसको भरने से रोक सकेंगे।

आज इंडियन ओशन से अमरीकन फ्लीट जा रहा है, यू के फ्लीट जा रहा है और उसकी जगह रशियन फ्लीट आ रहा है। लेकिन भारत सरकार कहती है कि हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। अरे, भाई यह हिन्द महासागर है, आप चाहें या न चाहें, इतिहास ने इसको हिन्द महासागर कहा है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे और अगर हिन्द महासागर के अन्दर रूस और चीन का प्रभाव बढ़ जायगा तो फिर याद रखिये भारत बच नहीं पायेगा इसलिए हिन्द महासागर हमारा है, हमारे पास है और वहां का वेकुअम हमें भरना चाहिए। वहां हम चीन और रूस को नहीं आने दे सकते। हमें अपनी विदेश नीति पर पुनरावलोकन करना होगा। जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उससे और नारों वाली विदेश नीति से हमारा काम नहीं बनेगा। फिर हमारी विदेश नीति चलाने वाले हैं कौन लोग? कभी मंत्री लोग पालिसी स्टेटमेंट दिया करते थे लेकिन अब हमारे जो सचिव हैं वह पालिसी स्टेटमेंट देते हैं। यह एक अनहोनी बात हमारे देश में इस समय हो रही है कि मंत्री के स्थान पर सेक्रेटरी पालिसी स्टेटमेंट कर रहे हैं। विदेश मंत्री कहां है? प्रधान मंत्री गूंगी हैं तो इसका क्या मतलब है कि प्रधान मंत्री के जो चेले हैं, चांटे हैं वह भारत की विदेश नीति की घोषणा करेंगे? हमारी प्रधान मंत्री भाई-भतीजावाद में विश्वास करती हैं। उनके पिता भी यही करते थे। परिणाम इस भाई-भतीजावाद का यह हो रहा है कि कोई कौल है, कोई धर है यह सब उसके इर्द-गिर्द इकट्ठा रहते हैं। अब क्या प्रधान मंत्री के यह नातेदार और रिश्तेदार जो भी उनकी मर्जी हो वैसा कर सकते हैं और कह सकते हैं? मेरी प्रधान मंत्री से मांग है कि वह अपने ऐसे सेक्रेटरियों को रोकें। वह इस प्रकार के पालिसी स्टेटमेंट मत करें। पालिसी स्टेटमेंट करने का काम दरअसल प्राइम मिनिस्टर का है। अभी हाल में हमारे नये विदेश मंत्री आये हैं। अच्छी बात है, मगर कोई कहता है कि वह इंदिरा गांधी की जेब में हैं तो कोई कहता है कि इंदिरा गांधी उनकी जेब में हैं। अब कौन किसकी जेब में है, मैं नहीं जानता। शायद दोनों श्री ब्रेझनेव की जेब में हैं। कौन किस की जेब में है मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं, लेकिन चिन्ता मुझे इस बात की है कि वह भारत के हितों की चिन्ता नहीं करते। आज दुर्भाग्य यह है कि हमारी विदेश नीति हमारे देश के हितों का विचार करके नहीं बनाई जा रही है। आज हमारी विदेश नीति रूस के इशारे पर चलती है। यह चीज ठीक नहीं है। रूस का रवैया क्या है? रूस भारत का दोस्त नहीं है। अभी वैगन डील के बारे में जो कुछ हुआ और बाकी बातों में जो कुछ रूस कर रहा

[श्री बलराज मधोक]

है उससे यह चीज स्पष्ट है कि न रूस और न ही अमरीका भारत के दोस्त हैं। दोनों ही भारत को कमजोर देखना चाहते हैं। वह जानते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि पोटेंशियल सुपर पावर बन सकता है। उसकी 50 करोड़ की आबादी है। उसके पास साधन हैं। इसलिए वह मुल्क नहीं चाहते कि भारत महाशक्ति बने और भारत महाशक्ति न बने इसके लिए वह पाकिस्तान को इस्तेमाल करते हैं। कभी अमरीका पाकिस्तान को बिल्ड करता है कभी रूस पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने के लिए बिल्ड करता है। इसलिए हमें इस पर विचार करना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी अमरीका से बिगड़े, मैं नहीं चाहता कि हमारी रूस से बिगड़े। हम दोनों से मित्रता चाहते हैं मगर मित्रता बराबर वालों में ही हुआ करती है। दो बराबरों में मित्रता होती है। मालिक और नौकर से मित्रता नहीं हुआ करती। मालिक और कुत्ते में मित्रता नहीं हुआ करती है। आज जो हमारी रूस से दोस्ती है वह बराबरी की दोस्ती नहीं है बल्कि वह मालिक और नौकर की दोस्ती है। मैं चाहता हूँ कि हमारी दोस्ती हो, लेकिन बराबरी की दोस्ती हो। भारत बलवान बने और वह सम्मान, हिम्मत व इज्जत के साथ अपने पैरों पर खड़ा हो। लेकिन अफसोस का विषय है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है। हालात यह है कि आज भारत की रूस पर निर्भरता है, आज अमरीका पर हमारी निर्भरता है। मैं चाहता हूँ कि हम अपने पैरों पर खड़े हों। वैसे कहने को तो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं मगर व्यवहार में हम देख रहे हैं कि हमारा विदेशी कर्जा बढ़ रहा है, पर-निर्भरता बढ़ रही है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि हमने पिछले साल अपने कर्जे पर 51 करोड़ 40 लाख डालर सूद दिया, 400 करोड़ रुपये से अधिक सूद दिया। आज भारत देश में जो बच्चा पैदा होता है वह अपने सिर पर कई सौ रुपये के कर्ज का भार लेकर पैदा होता है।

प्रधान मंत्री ने कल कहा था कि जो लोग कहते हैं कि हमने कोई तरक्की नहीं की वह ग़लत कहते हैं। तरक्की की है मगर आपकी जो तरक्की है उसकी तुलना उस खर्च से कीजिये जोकि आपने किया है। हमने 25,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किया है, 12,000 करोड़ का फौरेन लोन लिया, 5-6 हजार करोड़ की ऐड मिली। देश में इतने टैक्सेज़ बढ़ाये। उसके मुकाबले अब प्रगति हमने क्या की है ? प्रगति की तुलना हमेशा खर्चे से करनी चाहिए। देखना आपको यह चाहिए कि हमने खर्चा क्या किया, कोशिश कितनी की और उसके मुकाबले प्रगति क्या हुई ? यह मानना होगा कि जितना रुपया हमने खर्च किया उसके मुकाबले प्रगति कुछ भी नहीं हुई। जो मुल्क हमारे मुकाबले इंडस्ट्रियली और टेकनिकली पीछे थे, उतनी साइंस वहां पर ऐडवांस्ड नहीं थी वह मुल्क हमसे आगे निकल गये और हम पीछे रह गये।

देश को धोखा देना बंद कीजिये। मैं चाहता हूं कि भारत आगे बढ़े लेकिन भारत को आगे बढ़ाने के लिए आपको भारत की नीतियों के अन्दर मूलभूत परिवर्तन करना होगा। हमें भारत को किसी भी देश का पिछलग्गू नहीं बनाना है। हमें अपने देश की नीतियां इस देश के हित में और यहां की जनता के हित में बनानी होंगी और उसके अनुरूप ही अपनी विदेश नीति को ढालना होगा। अगर वैसा हम नहीं करेंगे तो फिर आर्थिक उन्नति होगी या नहीं होगी वह तो एक और बात है लेकिन यह चीज़ निश्चित है कि देश की एकता नहीं रहेगी।

आज पाकिस्तान और चीन में गठजोड़ है। वह मिलकर चल रहे हैं और देश के अन्दर जो उनके एजेंट हैं आज उनमें भी

गठजोड़ है। आज पाकिस्तानी तत्व, चीनी-रूसी तत्व, कम्युनिस्ट्स और पाकिस्तानी तत्व, इनमें गठजोड़ है। उनका यह गठजोड़ खुल्लमखुल्ला काम कर रहा है। यह गठजोड़ न केवल केरल के अन्दर काम कर रहा है, बल्कि वह सारे देश के अन्दर काम कर रहा है। इन चुनावों के अन्दर बिहार में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ यह एक साफ़ बात है। यह एक सबक़ है। मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से कहूंगा कि वे अपनी आंखें खोलें। देश के बाहर जो पाकिस्तान और चीन का एलाऐंस है, जो पिंडी पीकिंग ऐक्सिस है, उसी के नमूने पर इस देश के अन्दर कम्युनिस्ट्स और मुस्लिम लीग का एलाऐंस चल रहा है। परिणाम-स्वरूप देश में ऐंटी नेशनल फोर्सेज़ इकट्ठा हो रही हैं और वह देश की एकता, सुरक्षा व प्रभुसत्ता के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा बन रही हैं। उस ख़तरे का मुकाबला करने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

हमारे राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि यहां पर कुछ इंतहा पसन्द दल हैं जो कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते, जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और कि हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी को उनका नाम लेने में ज़रा संकोच हुआ। जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति का नाम लेने में संकोच करती है उसी प्रकार इस सरकार को ऐसे दलों का नाम लेने में संकोच होता है। अगर सरकार को संकोच नहीं है तो फिर उन दलों का नाम क्यों नहीं लेती जिनका कि लोकतंत्र में विश्वास नहीं है? कौन हैं जो कि यहां पर सशस्त्र क्रान्ति करना चाहते हैं? कौन हैं जो लोकतंत्रीय पद्धति का लाभ उठा कर, लोकतंत्रीय स्वतन्त्रता का लाभ उठा कर इस देश के अन्दर डेमोक्रेसी को ही खत्म करना चाहते हैं? स्पष्ट है कि वह कम्युनिस्ट हैं। और उन्होंने कभी इस चीज को छिपाया भी नहीं है कि उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। दरअसल उनका विश्वास वाएलेंस में है। वह देश के अन्दर ख़ूनी क्रान्ति चाहते हैं। वह लोकतंत्र की जो ताकत है उसका लाभ उठाकर उसको एक्सप्लाएट करके देश की जो मूलभूत एकता है उसे वह नष्ट करना चाहते हैं। आप उन पर रोक लगाने को तैयार नहीं, उनका नाम लेने को भी तैयार नहीं। मैं मांग करता हूं कि अगर इस देश की एकता को बचाना है, इस देश की आजादी व इज्जत को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसी घातक व विघटनकारी शक्तियों को देश में पनपने नहीं देना चाहिए।

मैं यह मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपने ढंग से काम करने का अधिकार है, पार्टी आदि संगठित करने का भी अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र के अन्दर किसी ऐसी पार्टी को जिसका कि वास्तव में लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है वैसी किसी पार्टी को बने रहने का अधिकार नहीं हो सकता है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में यह भी कहा है कि हर एक व्यक्ति के अन्दर सैकुलरिज्म और नेशनलिज्म की भावना पैदा करनी चाहिए। क्या आपने कभी गम्भीरता से सोचा है कि नेशनलिज्म होती क्या है? इस देश के अन्दर रट तो आप अवश्य इस नेशनलिज्म की लगाते हैं लेकिन उसका दरअसल मतलब क्या है इसे भी क्या कभी आप ने समझने की कोशिश की है? नेशनलिज्म कोई नई कल्पना नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है। दुनिया भर में यह कंसेप्ट चलता है। आज के युग में नेशनलिज्म एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि उसका आधार क्या है? नेशनलिज्म का आधार मजहब नहीं होता। नेशनलिज्म का आधार यह होता है कि सभी लोग चाहे वह किसी जाति, सम्प्रदाय या संस्था के हों सभी को

[श्री बलराज मधोक]

इस देश से प्यार हो। हर एक देशवासी को इस देश की संस्कृति व परम्परा से प्यार हो। उनका मज़हब कुछ भी हो, उनका प्रान्त कुछ भी हो, उनकी जाति कुछ भी हो, लेकिन वह सब देश से प्यार करें और ऐसा होने से वह एक राष्ट्र बनता है इसलिए हर एक देशवासी की राष्ट्र के प्रति आस्था सर्वोपरि होनी चाहिए। एक राष्ट्र में कई ग्रुप्स हो सकते हैं, पोलिटिकल पार्टियां होती हैं, प्रान्त, सम्प्रदाय व भाषाएं होती हैं। वे सब हमारे देश में भी हैं और हर व्यक्ति का किसी पोलिटिकल पार्टी या सम्प्रदाय से लगाव हो सकता है, उस विशेष सम्प्रदाय या भाषा के प्रति उसकी आस्था भी हो सकती है और होती है। साधारणतया इन आस्थाओं में और राष्ट्र के प्रति आस्था में कोई टकराव नहीं होना चाहिए।

कोई व्यक्ति नैशनल है या कम्यूनल है, कोई पार्टी नैशनल है या कम्यूनल है, यह सवाल तब पैदा होता है जब इन आस्थाओं में टकराव हो, हमारी पार्टी के हितों और देश के हितों में टकराव हो, हमारे साम्प्रदायिक हितों और देश के हितों में टकराव हो, क्षेत्रीय हितों और राष्ट्र के हितों में टकराव हो। जिस समय कोई पार्टी या कोई व्यक्ति यह कहे कि हमारा देश पहले आता है, हम देश के लिए जियेंगे और मरेंगे, हम देश के लिए अपनी पार्टी के हितों को, अपने सम्प्रदाय के हितों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, तो वह राष्ट्रीयता है, वह कौमपरस्ती है। लेकिन जो यह कहता है कि देश चूल्हे में जाये, हमारी पार्टी पहले है, हमारा प्रान्त पहले है, और अपने सम्प्रदाय या जाति के लिये देश के हितों को नुक्सान पहुंचाने के लिए तैयार हो, तो वह सम्प्रदायवाद होता है, वह कम्यूनलिज्म होता है, वह फिरकापरस्ती होती है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may continue after Lunch. The House stands adjourned till 2.00 P.M.

13. hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

---

14. 05 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Luuch at Five Minutes Past Fourteen of the Clock.

[SHRI GADILINGANA GOWD *in the Chair.*]

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENTS ADDRESS *Contd.*

श्री बलराज मधोक : सभापति महोदय, मैं यह कह रहा था कि संसार भर में राष्ट्रीयता का एक ही आधार है, एक ही कसौटी है कि जो राष्ट्र को आगे रखे वह राष्ट्रवादी है और जो अपने दल को या अपने प्रान्त को या अपने सम्प्रदाय को आगे रखे, वह राष्ट्रवादी नहीं है, वह सम्प्रदायवादी है। यही कसौटी जर्मनी में लागू की जाती है और यही कसौटी फ्रांस में लागू की जाती है। यह कसौटी पूरे भारत में भी लागू की जानी चाहिए।

मैं चाहूंगा कि हमारे कांग्रेसी सदस्य इस कसौटी पर अपने दल को कसें और भारतीय जनसंघ को भी कसें। मुझे इस बात का गर्व है कि भारतीय जनसंघ ने अपने पिछले सतरह साल के इतिहास में कभी भी देश के हितों को नुक्सान नहीं पहुंचाया है। हमारे लिए देश पहले आता है और दल बाद में। हमारे लिए दल केवल राष्ट्र सेवा का एक माध्यम है। हमारे प्रवर्तक और हमारे निर्माता डा० मुकर्जी ने देश की एकता के लिए काश्मीर में जाकर पहला बलिदान दिया। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने कदम-कदम पर अपने दलगत स्वार्थों के लिए देश के हितों को नुक्सान नहीं पहुंचाया है और आज

भी नहीं पहुँचा रही है ? क्या इस देश के अन्दर पृथकतावाद की भावना को, क्षेत्रवाद की भावना को कांग्रेस ने नहीं भड़काया है ? आज पंजाब में क्या हो रहा है ? पंजाब के अन्दर आप लोगों ने भाई-भाई के अन्दर फूट डाली । भारतीय जनसंघ को गर्व है कि उसने अपने जिन भाइयों को अलग-अलग किया था, उनको फिर जोड़ा है । आज कांग्रेस वाले फिर वहां पर सिख नान-सिख का सवाल उठा रहे हैं, उनके अन्दर अलगाव की भावना पैदा कर रहे हैं । कभी हिन्दी के नाम पर ऐसा कर रहे हैं और कभी किसी और नाम पर । कदम-कदम पर अलगाव की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं । पिछले दिनों प्रधान मंत्री ने पंजाब का दौरा किया था । तब उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया गया तो काश्मीर भारत में नहीं रहेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि काश्मीर का इलहाक भारत से साथ हुआ है या प्रधान मंत्री के साथ हुआ है या कांग्रेस के साथ हुआ है ? क्या यह काशमीर की जनता को उकसाना नहीं है कि अगर कांग्रेस पावर में नहीं आई तो तुम अलगांव की अपनी मांग को उठाना ।

आज कांग्रेस इज़राइल को इसलिए मान्यता नहीं दे रही है कि कहीं हिन्दुस्तान के मुसलमान वोटर उससे बिदक न जाएं । यह मेरा कहना नहीं है और लोगों का भी यह कहना है । राजस्थान यूनिवर्सिटी के डा० माथुर ने भी अपनी अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की किताब में यह लिखा है कि भारत सरकार इज़राइल को इसलिए मान्यता नहीं देती है कि कहीं यहां के मुसलमान वोटर्ज कांग्रेस से बिदक न जायें । जो पार्टी अपनी नीतियों और अपने कार्यक्रम में हर समय साम्प्रदायिकता का प्रचार करती है, साम्प्रदायिकता को उभारती है वह जनसंघ को कम्युनल कहे, इसी को कहते हैं, उलटा चोर कोतवाल को डाटे । जो खुद शीशे के मकान में रहता है वह पत्थर हम पर फेंके जिसका मकान स्टील का बना हुआ है, तो इसका कुछ भी नतीजा नहीं निकल सकता है । आज हिन्दुस्तान में कोई राष्ट्रवादी दल है तो वह भारतीय जन संघ है । भारतीय जन संघ का इतिहास इसका साक्षी है । जो चांद पर थूकता है, वह अपने मुंह पर थूकता है । भारतीय जन संघ की राष्ट्रीयता की कल्पना आपकी जो राष्ट्रीयता की कल्पना है उससे भिन्न है । भारत में कई मजहबों के लोग बसते हैं । किसी दल में किसी खास मजहब के या मत के लोग आएं तो ही वह दल राष्ट्रीय हो सकता है अन्यथा नहीं यह सरासर गलत है । कहीं भी यह परिभाषा राष्ट्रवादी होने की नहीं है, राष्ट्रीयता की नहीं है । राष्ट्रीयता का अर्थ देखना हो तो उसका अर्थ आप डिक्शनरी में या एनसाइक्लोपीडिया में देखिये । संसार भर में राष्ट्रीयता का जो अर्थ लागू होता है वही आप भारत में भी लागू करें । यदि आपने ऐसा किया तभी आप देश की राष्ट्रीयता को बचा पाओगे ।

आज भारत को राष्ट्रीयता की जरूरत है । भारत में जो अलगाव की शक्तियां बढ़ रही हैं, सिर उठा रही हैं, उनका मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीयता ही आज कारगर हो सकती है । हमको राष्ट्रीयता को जगाना होगा । राष्ट्रीयता जागी थी जब चीन ने भारत पर हमला किया था, पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था परन्तु वह आपके द्वारा नहीं जागी थी, भारतीय जनसंघ ने ही उसको जगाया था । आज भारतीय जन संघ भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत है । आपसे कुछ नहीं बनने वाला है । भारतीय जन संघ राष्ट्रवाद के लिए जो प्रयत्न आज तक करता रहा है, उसको वह जारी रखेगा, और उसी के द्वारा भारत का राष्ट्रवाद पनपेगा ।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सेक्युलरिज्म का जज़बा पैदा करना चाहिए,

[श्री बलराज मधोक]

यह बात भी कही गई है। सैक्युलरिज्म का अर्थ क्या है ? क्या आप सैक्युलर हैं ? सैक्युलरिज्म का अर्थ यह नहीं होता है कि राज का धर्म न हो। आज ब्रिटेन एक सैक्युलर स्टेट है। लेकिन वहां का राज धर्म है। वहां का राजा एंगलिकन चर्च का होता है और स्टेट फंड्ज से चर्च डिगनिटरीज को पे मिलती है। अमरीका भी एक सैक्युलर देश है लेकिन उसका भी राज धर्म है। जिसका राज धर्म कोई न हो वही सैक्युलर है, यह सैक्युलरिज्म का अर्थ नहीं है। सैक्युलरिज्म का अर्थ यह होता है कि जो राज्य है जो स्टेट है वह अपनी जनता के बीच में, पूजा विधि के आधार पर मज़हब के आधार पर, पैट्रेनेज के मामले में, नौकरियों के मामले में, कानून के मामले में कोई भेदभाव न करे।

संसार भर में सैकुलरिज्म का यही अर्थ माना जाता है। लेकिन क्या सरकारी दल और यह सरकार इस अर्थ को मानती है ? नहीं। अगर वे सैकुलर होते, तो क्या इस देश में हिन्दू के लिये एक मैरिज ला और मुसलमान के लिये दूसरा मैरिज ला होता ? आप मुझे संसार का कोई ऐसा सैकुलर देश बता दीजिए, जिसमें अलग-अलग सम्प्रदायों के लिए अलग-अलग मैरिज लाज़ हैं।

इनका माडल अशोक है, जो कि हमारे इतिहास में एक ही राजा हुआ, जो सैकुलर नहीं था। हमारे देश के तीन बड़े इतिहास-कारों, रे चौधरी, मोजमदार और दत्त ने लिखा है :

> "Because Ashok fell from the secular ideal of Hindu State, that created a reaction and became a major reason for the fall of the Mauryan empire"—

हमारे इतिहास में जो एक राजा सैकुलर नहीं था, वह इन का माडल है। वास्तव में ये लोग सैकुलर नहीं हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सैकुलर बनें। मैं और मेरी पार्टी सैकुलर हैं। हमारा मत है कि हिन्दुस्तान उसी प्रकार एक हिन्दू स्टेट है, जिस प्रकार यू० ए० आर०, सीरिया और सूडान मुस्लिम स्टेट्स हैं और ब्रिटेन एक क्रिस्टियन स्टेट है। सीरिया में 14 परसेंट, सूडान में 14 परसेंट और यू० ए० आर० में 12 परसेंट नान-मुस्लिम्ज़ हैं, लेकिन वहां पर किसी ने कभी रिलिजस माइनारिटी की बात नहीं सुनी, हालांकि वे मुस्लिम स्टेट्स कहलाती हैं और अपने आप को सैकुलर कहती हैं। लोक-तन्त्र में सिर्फ पोलीटिकल मैजारिटी और माइनारिटी की बात कही जाती है। इस देश में इन लोगों की तरफ से सैकुलर स्टेट होने का दावा किया जाता है, लेकिन हर रोज़ रिलीजस माइनारिटी की बात उठाई जाती है। यह ठीक नहीं है।

कांग्रेस आज मैजारिटी में है और हम माइनारिटी में हैं। कांग्रेस का फ़र्ज है कि वह देश में स्वस्थ परम्परायें कायम करे। लेकिन ये लोग एक तरफ़ तो अपने दलगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए मज़हबी भावनाओं को उभारते हैं और दूसरी तरफ सैकुलरिज्म की रट लगाते हैं। और यह सैकुलरिज्म की रट उस देश में लगाई जाती है, जिसमें कभी थ्यूरोक्रेसी नहीं थी। मैं समझता हूं कि भारत में सैकुलरिज्म की बात करना भारत का अपमान करना है, भारत की प्राचीन परम्पराओं और संस्कृति का अपमान करना है। जैसा कि मैंने कहा है, भारत कभी भी थ्यूरोक्रेसी नहीं था और न ही होगा, जब तक कि यहां पर भारतीय और वैदिक संस्कृति रहेगी। प्रधान मंत्री तो कुछ पढ़ती-लिखती नहीं हैं। इन लोगों में से जो पढ़े-लिखे हैं, वे इन बातों का अध्ययन करें, इन शब्दों के अर्थ को समझें और तोते की तरह किन्हीं बातों की रट न लगायें। वे शब्दों के अर्थ को समझ कर वास्तविक अर्थों में सैकुलर बनने की कोशिश करें।

इस अभिभाषण में राज्यों के साथ अच्छे

सम्बन्ध बनाये रखने की बात कही गयी है। लेकिन केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों के साथ क्या सलूक कर रही है? वह कैसी लोकतन्त्रीय परम्परायें स्थापित कर रही है? लोकतन्त्र केवल संविधान के आधार पर नहीं चलता है। वह ठीक और स्वस्थ परम्पराओं के आधार पर चलता है। लेकिन यह सरकार कैसी परम्पराएं डाल रही है? हरियाणा में उसने कौनसी परम्परा डाली है? एसेम्बली में अपनी मैजारिटी बनाये रखने के लिए चार मेम्बरों को हाउस से ससपेंड कर दिया गया। क्या यह लोकतन्त्र है? यहाँ पर एक मेम्बर को किडनैप कर दिया गया। क्या यह एक लोकतन्त्रीय परम्परा है?

SHRI S. M. BANERJEE: (Kanpur): On a point of order. We are discussing a very important matter. At least some Cabinet Ministers should be present when the President's address is being discussed. A leader of an Opposition Party is speaking now. But neither the Prime Minister, nor the Deputy Minister, nor the Home Minister is present. There is a bunch of Cabinet Ministers Where are they and what are they doing ?

MR. CHAIRMAN: They will come. The hon. Member may continue.

श्री बलराज मधोक : दुर्भाग्य यह है कि यहां के मंत्रियों को इस पार्लियामेंट की गरिमा की चिन्ता नहीं है, उनको लंच की चिन्ता ज्यादा है। वे लंच खाने गये हुए हैं। काश, उनको पार्लियामेंट की चिन्ता होती, उनको संविधान का पास होता।

दिल्ली के साथ केन्द्रीय सरकार क्या सलूक कर रही है? दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन चूंकि उसका प्रशासन जनसंघ के हाथ में है, इसलिए उसके साथ सौतेली मां का सा सलूक किया जा रहा है, उसको सब साधनों से वंचित किया जा रहा है। यह शर्म की बात है।

दिल्ली में जो सरकारी कर्मचारी हैं, आज उनकी हालत क्या है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज सरकारी कर्मचारियों की रीयल वेजिज 1947 की तुलना में कम हैं, जबकि यह सरकार देश की प्रगति की बात करती है। जहाँ तक दिल्ली की आवास-समस्या का सम्बन्ध है, यहां पर लगभग दो-सौ तथाकथित अनधिकृत बस्तियां हैं। लोगों ने अपने गहने बेच कर, तरह-तरह की मुसीबतें उठाकर अपने छोटे-छोटे मकान बनाये हैं। यह सरकार खुद तो किसी को मकान दे नहीं सकती है, लेकिन वह उन मकानों को तोड़ने पर तुली हुई है। वह देश की राजधानी में साधारण सुविधायें भी नहीं दे सकती है। यह ढंग नहीं है हुकूमत करने का। शासनारूढ़ दल का कर्त्तव्य है कि वह दूसरे दलों के लिए, देश के विभिन्न राज्यों के लिए, एक माडल पेश करे, उनके लिए एग्जाम्पल सेट करे।

यह गांधी सेनटेनरी ईअर है। इस अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हम गांधीजी को राष्ट्रपिता कहते हैं। ऐसा करके हम उनका अपमान करते हैं। अगर गांधीजी आज जीवित होते, तो वह इन लोगों पर लानत भेजते कि ये क्या कर रहे हैं। गांधीजी इस देश के महान् सपूत थे, वह इसके पिता नहीं थे। हमारा राष्ट्र 1921 में नहीं बना। हमारा एक प्राचीन राष्ट्र है। गांधी जी इस देश के महान सपूत थे, जैसे कि राम इस देश के महान् सपूत थे। भारत माता सबकी मां है। उसका कोई बाप नहीं हो सकता है। गांधीजी को राष्ट्रपिता कह कर उनका अपमान नहीं करना चाहिए।

गांधीजी इस देश में क्या व्यवस्था चाहते थे? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को तोड़ डालो और उसमें जो अलग-अलग विचारधारा के लोग हैं, वे अपने अलग-अलग दल बना लें। कांग्रेस ने गांधीजी की बात

[श्री बलराज मधोक]

नहीं मानी। अब भी वक्त है कि कांग्रेस गांधीजी की बात को मान ले। कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं है, दो पार्टियां हैं : एक नेहरूवादी और दूसरी पटेलवादी। नेहरूवादी रूस का चरण-चुम्बन करते हैं, कम्युनिस्टों की तरफ देखते हैं। पटेलवादी लोकमान्य तिलक, लाला लाजपतराय, महामना मालवीय, विपिनचन्द्र पाल और सरदार पटेल की परम्पराओं पर चलते हैं। आज उनकी ज़बान बन्द है। अब समय आ गया है कि वे अपनी आवाज़ उठायें। आज देश की एकता, प्रभुसत्ता और सुरक्षा खतरे में है। जिनके हाथ में उन्होंने हुकूमत दे रखी है, वे इस देश को बेचने पर तुले हुए हैं।

आज लड़ाई जनसंघ और कांग्रेस की नहीं है, लेफ्ट और राइट की भी नहीं है। वास्तव में लड़ाई राष्ट्रवादियों और राष्ट्रद्रोहियों की है, लोकतंत्रवादियों और लोकतंत्र के विरोधियों की है। आज लोकतंत्र-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी इकट्ठे हो रहे हैं। उनका गठजोड़ केरल में, बंगाल में और यहां भी दीख रहा है। इसलिए लोकतंत्र-विरोधियों और राष्ट्र-विरोधियों के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रवादी और लोकतंत्रवादी शक्तियों को मिलकर काम करना होगा। देश जनसंघ से बड़ा है। देश कांग्रेस से बड़ा है। आज जबकि देश पर संकट है, हमें इस बात पर विचार करना चाहिए।

मुझे आशा है कि मैंने जो कुछ कहा है, जो कुछ आलोचना की है, कांग्रेस के बन्धु और राष्ट्रवादी कांग्रेसी गम्भीरता से उस पर विचार करेंगे और उस पर अमल करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के लिए सदन के सामने जो धन्यवाद-प्रस्ताव श्रीमती सुशीला रोहतगी ने रखा है, मैं उस का अनुमोदन करता हूं।

अभी सदन के एक बड़े अच्छे नेता, एक पार्टी के नेता, श्री बलराज मधोक बोले हैं। मैंने उन की बातों को बड़े ध्यान से सुना है। लेकिन उन के बारे में मैं बाद में कहूंगा।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं और भारत सरकार की नीतियों का संक्षेप में वर्णन किया है। उन्होंने खेती-बाड़ी, परिवार-नियोजन, उद्योग, आयात-निर्यात, टूरिज्म, सिंचाई, पब्लिक सेक्टर, सेकुलरिज्म, योजना कमीशन, सरकारी कर्मचारियों के साथ ताल्लुकात, विदेश नीति, जंगी फ़ौजों, फ़ौजी अख़राजात, मध्यवर्ती चुनाव, विदेशी इमदाद और कर्जे, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं वग़ैरह की तरफ़ संसद् का ध्यान आकर्षित किया है।

आज देश के सामने बेरोज़गारी, ग़रीबी, जहालत और मंहगाई की समस्यायें हैं, जो सारी जनता को बहुत परेशान कर रही हैं। इस के साथ ही सब से बड़ी समस्या है अनुशासनहीनता की, जो बढ़ती चली जा रही है। (**व्यवधान**) इस समस्या को पैदा करने वाले श्री एस० एम० बनर्जी भी हैं, जो यहां पर अनुशासनहीनता कर रहे हैं।

जनता अपने प्रतिनिधियों को यहां पर इस लिए भेजती है कि वे यहां आकर उनकी भावनाओं का ख़याल रखें और उनकी मुश्किलों और तकलीफ़ों और उनकी समस्याओं का हल ढूंढें, उन पर विचार करें और उनके दुखों का निवारण करें। लेकिन विधान सभाओं में, लोक सभा में भी अधिकतर और सामने वाले पक्ष में तो बहुत ज्यादा, सदस्य ऐसे हैं,—मैं अपने आप को उन में शामिल करता हूं—जो कि अपने दुख का निवारण करने के लिए कोशिश करते हैं। उन का जो अपने घर का दुख है वह कुछ भी हो, शक्ति का

हो, ताकत का हो और किसी चीज का हो उसको निवारण करने के लिए वह सबसे पहले प्रयत्न करते हैं। अगर यह बात न हो तो इस सदन के अन्दर जनता की समस्याओं पर विचार किया जाय और यह न कहा जाय कि प्रधान मंत्री जी पढ़ती नहीं हैं, लिखती नहीं हैं, प्रधान मंत्री जी की फलानी बात है। यह बातें देश की प्रधान मंत्री के बारे में नहीं कही जानी चाहिएं। लेकिन अपोज़ीशन वालों के पास और कोई बात कहने को नहीं है। उनके पास केवल एक बात है कि दूसरे की आलोचना करनी है केवल आलोचना के लिए।

सभापति महोदय जब यह बाहर जाते हैं तो इन का रवैया कुछ और होता है और यह कुछ और बातें कहते हैं। लेकिन जब सदन में आते हैं तो इन की बातें और इन का रवैया, इन की नीति, इन की भाषा बिलकुल एक अलग होती है। वह आप देखते रहते हैं। आप ने देखा होगा कि मेरे दोस्त ने अभी बहुत कुछ कहा है। राष्ट्रीयता का उदाहरण दिया है और कहा है कि हम राष्ट्रवादी हैं क्योंकि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है और जब बाहर जाते हैं, वोटर के पास जाते हैं तब यह कहते हैं कि हमारे मुसलमान भाई हैं, हम सब एक हैं, हिन्दुस्तान सब का है। यहां आते हैं तो क्योंकि गवर्नमेंट को बुरा कहना है तो कहते हैं कि हिन्दुस्तान हिन्दुओं का है...

श्री बलराज मधोक : गलत बात मेरे मुख में मत डालिए। जो मैंने कहा है वह कहिए।

श्री प्रेम चंद वर्मा : मैं यह जानता हूं कि इन विरोधी दलों के जो लोग हैं, हम दो और दो चार कहेंगे तो इन्होंने दो और दो तीन कहना है, पांच नहीं कहना है न चार कहना है। क्योंकि इन की आंखें पीछे की तरफ हैं आगे की तरफ नहीं। ऊपर की ओर या आगे की ओर यह नहीं देखते हैं। यह पिछली शताब्दी की ओर, 18वीं शताब्दी की ओर निगाह रखते हैं...

श्री स० मो० बनर्जी : और आपका दिमाग है आसमान पर और पैर हैं धरती पर।

श्री प्रेम चंद वर्मा : मैं एस० एम० बनर्जी साहब से अर्ज करूंगा कि वह घबरायें नहीं, मैं अभी उनकी बात पर भी आता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं, जम्हूरियत में वास्तविकता को झुठलाया नहीं जा सकता। जो सच्चाई है वह सच्चाई है। जो वास्तविकता है वह वास्तविकता है। लेकिन इनको सच्चाई से, वास्तविकता से किसी बात से गरज नहीं है। अगर सरकार की खामियां हैं, सरकार की नीतियों में खामियां हैं तो यह इन का कर्त्तव्य बन जाता है कि वह सरकार को ठीक ढंग से उन नीतियों में परिवर्तन करने के लिए कहें क्योंकि अपोजीशन का यह एक रोल होता है कि वह सरकार की नीतियों पर कटाक्ष करे और अगर नीतियां गलत हैं तो उनको बदलने का प्रयत्न ठीक ढंग से करे, किसी के व्यक्तित्व पर हमला न करें।

सभापति महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि देश का बच्चा-बच्चा यह समझे कि यह दिन अमन के हैं। हम आज लड़ाई में नहीं हैं। इन अमन के दिनों में, शांति के दिनों में देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश का डेवलपमेंट किया जा सकता है। देश को विकास की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कैसे ? वह तभी हो सकता है कि जो दल राज्य करता है, उस दल को विरोधी दलों की ओर से भी सहयोग मिले, उसको उस काम में आगे बढ़ाने के लिए उनकी ओर से भी कुछ मदद मिले। मगर जबकि आज यहां यह हर रोज कहते हैं कि हमारी सरहद

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

पर पाकिस्तान खड़ा है, हमारी सरहद पर चीन खड़ा है, ठीक है, हम भी जानते हैं, लेकिन आज वह टाप टाइम है कि हम उन दुश्मनों के मुकाबिले के लिए इस देश को तैयार करें और देश तब तैयार हो सकता है, नारे देने से देश कभी तैयार नहीं हो सकता है, देश तैयार होता है काम करने से, देश तैयार होता है मेहनत करने से, देश तैयार होता है एकता से। लेकिन वह बातें तो हैं ही नहीं। तो हिन्दुस्तान में अगर प्रजातंत्र को जीवित रखना है, हिन्दुस्तान की अखंडता को अगर कायम रखना है तो विरोधी दलों को अपने दिल, अपने तौर तरीके बदलने होंगे, अपनी नीतियां बदलनी होंगी और उनको यह समझना होगा कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है ? जब तक वह ऐसा नहीं करते हैं तब तक वह अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह से निभा नहीं सकते हैं। भारत की यह बदकिस्मती है (**व्यवधान**) ··· मुझे डिस्टर्ब करने से आप को फायदा होने वाला नहीं है बल्कि उलटे नुकसान हो सकता है। मैं यह कह रहा था कि भारत की बदकिस्मती है कि यहां कोई ऐसी अमली अपोजीशन पार्टी नहीं है। अगर एक अमली अपोजीशन पार्टी होती तो वह अपने फर्ज को अच्छी तरह निभाती, अपने काम को उचित ढंग से करती। लेकिन यहां तो बात यह है कि जो व्यक्ति सत्ता का भूखा है वह अपना एक दल खड़ा कर लेता है, अपना झंडा बुलंद कर देता है। आपने देखा होगा केरल में, बंगाल में, उड़ीसा में, तामिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में क्या हुआ ? इन प्रान्तों की हालत देखिए। तीस-तीस पार्टियों ने एलेक्शन लड़ा है। जहां 280 सीटें हों और तीस-तीस पार्टियां लड़ें वहां पर कोई स्थायी सरकार बन सकती है ? कभी नहीं बन सकती। इसलिए हम को यह सोचना होगा, सरकार को यह बात सोचनी होगी कि यह राजनीतिक दल कम से कम हों। विरोध कीजिये आप, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। डेमोक्रेसी है, इसमें जिसको वोट मिलेंगे वह सत्ता पर आरूढ़ हो सकता है। लेकिन इस तरह का जो एक वातावरण पैदा हो रहा है कि इन्हीं का साथी, हमारे में से गया हुआ चरण सिंह, उसे इन्होंने छाती से लगाया और सिर पर उठाया, उसके पांव इनके सिर पर रहे, आज वह इनको जूतियां लगाकर इनसे बाहर जाकर खड़ा हो गया, उसके 98 आदमी आए और इनके पचास भी नहीं रहे। वह इनको नीचे फेंककर खुद आगे चला गया। यह तो इन की हालत है। यह इसलिए कि हमारा जो आदमी था चरण सिंह, कांग्रेस का आदमी, उसको तोड़ कर अपने सिर पर रखने में उन्होंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो यह तो इनकी बात है। लेकिन जो जातीयता के आधार पर, सूबाई क्षेत्रों के आधार पर, इन छोटी-छोटी बातों को लेकर पार्टियां और दल बन रहे हैं इनको रोकने की आवश्यकता है। हिन्दुस्तान का भला तभी हो सकता है जब यह राजनीतिक दल कम से कम तादाद में हों और सरकार को चाहिए कि किसी भी तरीके से इन को कम करने के लिए कदम उठाए। सभी पार्टियों को भी चाहिए कि इन को कम करने के लिए कोशिश करें···

श्री हुकमचंद कछवाय : कांग्रेस को खत्म कर दो, सब ठीक हो जायगा।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : कांग्रेस आपके कहने से तो खत्म नहीं होगी। कसाई के कहने से भैंस नहीं मरा करती है। तो राजनीतिक दलों की यह जो एक बाढ़ आ गई है इसको रोकने की आवश्यकता है। सरकार को यह सोचना है और मैं तो यह कहता हूं कि इन का हाल तो यह है कि कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा।···

श्री हुकम चन्द कछवाय : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है।

राष्ट्रपति जी के भाषण पर हम बहस कर रहे हैं और एक भी कैबिनेट का मंत्री यहां नहीं है। इस प्वाइंट को पहले भी रेज़ किया गया है। आप उनको बुलाइए उसके बाद कार्य-वाही होगी। ···(**व्यवधान**) ···सभापति महोदय, आपको ध्यान होगा कि जब यहां पर श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे उस समय यह बात उठाई गई थी और अध्यक्ष की रूलिंग इस बारे में है कि कैबिनेट मंत्री यहां पर होना चाहिए।

श्री प्रेम चंद वर्मा : सभापति जी, असल में बात यह है कि मेरे दोस्त यह समझते हैं कि इनकी नब्ज़ पर मैंने हाथ रख दिया है तो नब्ज पर से मेरा हाथ हटाना चाहते हैं, लेकिन मैं हटाने वाला नहीं हूं। मुझे मालूम है कि असल बीमारी क्या है।

तो मेरी राय यह है और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह बहुत से दलों की जो बाढ़ आ गई है मेढ़कों की तरह से इनको खत्म करके ज्यादा से ज्यादा 4 दल रहने चाहिएं। एक लेफ्ट, एक राइट, सेंट्रलिस्ट और चौथा जो है उस में बाकी जो कहीं फिट न हों वह उसमें चले जायं। एक चौथा दल ऐसा बनना चाहिए जिस में तीनों दलों में जो कहीं फिट न आता हो वह उस चौथे दल में चला जाय। इस से ज्यादा दल नहीं होने चाहिएं ··· (**व्यवधान**) ··· और उसका प्रधान कछवाय को बना देना चाहिए।

अब मैं बेसिक पालिसियों की ओर आता हूं। गरीबी और अमीरी के फर्क को दूर करने के लिए हमें बेसिक नीतियों में तब्दीली लाने की जरूरत है ताकि अमीर, ज्यादा अमीर और गरीब, ज्यादा गरीब न होता चला जाय। वह तमाम काम हमें करने चाहिए जिससे अमीर लोग गरीबों का शोषण न कर सकें।

न ही पूंजीपति राजनीति में अपना प्रभाव डाल सकें। अगर ऐसी व्यवस्था हो जाय तो इससे कई समस्यायें हल हो सकती हैं। अगर इन लोगों को सरकार की नीतियों पर असरअन्दाज होने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो मैं समझता हूं कि इससे देश का बहुत लाभ होगा।

सोशलिज्म लाने के लिये सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं और उन नीतियों में से जो गलत साबित हुई हैं, उन पर सरकार फिर से गौर करे। पांच साला प्लान जो बनते हैं, उनके बारे में देखा जाय कि जनता को उनका लाभ मिले, न कि ऐसे लोगों को जो पूंजीपति हैं। आज पूंजीपति हमारी इन योजनाओं का अनुचित लाभ उठा रहे हैं।

पिछड़े क्षेत्र और पिछड़े वर्ग जो हैं, उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। हरिजन, आदिवासी, छोटे-छोटे किसान जिनके पास छोटी-छोटी जमीनें हैं, उनको छोटी-छोटी इण्डस्ट्रीज़ में लगाने के लिये गांवों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिये। इसके साथ ही सरकार को इस बात की तरफ भी ध्यान देना होगा कि गरीबों और छोटे-छोटे लोगों को ये पूंजीपति, और इन पूंजीपतियों की पोलिटीकल पार्टीज़ गुम-राह न कर सकें।

अब मैं हिमाचल प्रदेश की समस्याओं की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को मुकम्मिल सूबे का दर्जा दिया जाय और जब तक हिमाचल प्रदेश केन्द्र-शासित प्रदेश है, उसके डवेलपमेन्ट के लिये मौजूदा रकम से कम-से-कम 25 फीसदी ज्यादा रकम दी जाय ताकि इस पिछड़े हुए पहाड़ी प्रदेश को देश के दूसरे हिस्सों के बराबर तरक्की करने का मौका मिल सके। पीने के पानी और सिंचाई की स्कीमों के लिये कम-से-कम पांच करोड़ रुपया अलग से रखा जाय। टूरिज्म को डेवलप करने के लिये काश्मीर के बराबर हिमाचल-प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों पर खर्च किया जाय। गोविन्द सागर झील को खास तौर पर डवेलप किया जाय। हिमाचल प्रदेश, पंजाब,

[श्री प्रेम चन्द वर्मा]

हरियाणा, जम्मू-काश्मीर और दिल्ली का एक फूड-ज़ोन रखा जाय ताकि 1967 के हालात फिर पैदा न हों। पंजाब की फ्रन्ट की वज़ारत को फूड-ज़ोन में गड़बड़ पैदा करने की इजाजत न दी जाय और उससे कहा जाय कि हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को पंजाब में मिलाने के लिये जो लोग मुतालबा करते हैं, उनको शह देना बन्द कर दे।

सभापति जी, बदकिस्मती है कि मेरी पार्टी के एक सदस्य ने, जो बहुत पुराने सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कल एक बात कही, जिसका मुझे जवाब देना पड़ रहा है। कल उन्होंने कहा था कि प्रधान मंत्री जी गांधी जी के रास्ते को छोड़ कर अपने लिये मकान बनाने पर 25 लाख रुपया खर्च कर रही हैं, ऐसा उनको नहीं करना चाहिये। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिन पार्टी से वह ताल्लुक रखते हैं, प्रधान मंत्री जी उसी पार्टी की नेता हैं और उन्हीं के साथ में पली हैं, फिर भी वह कहते हैं कि राष्ट्रपति भवन के एक कोने में उनको जगह मिले। अगर सेठ जी यहां मौजूद हों, तो उन तक मैं अपनी आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, उनका अपना मकान जबलपुर में कितना शानदार है, जबकि प्रधान मंत्री एक ऐसी कोठी में रहती हैं जोकि एक डिप्टी मिनिस्टर के स्टेण्डर्ड की कोठी है। उनकी कोठी के चार कमरे सेठजी की कोठी के एक बैड-रूम के बराबर हैं, मैं यह उन की जबलपुर की कोठी की बात बतला रहा हूं। अगर हम दूसरों को क्रिटि-साइज करें, तो पहले अपने आपको भी देखना चाहिये।

सभापति जी, आपकी पार्टी के आचार्य रंगा साहब की मेरे मन में बहुत इज्जत है, अपने बाप से कम मेरे मन में उनकी इज्जत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस में काम किया है और किसानों के लिए जो काम किया है, शायद देश में दूसरे किसी नेता ने उतना काम नहीं किया है। वह आज तक किसानों के लिए लड़ते रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती इस देश की यह है कि आज वह ऐसे लोगों के पंजों में जा फंसे हैं जो किसानों के दुश्मन हैं, आज वह सरमायेदारों के तबके में जा फंसे हैं और मैं समझता हूं कि शायद उसी पार्टी के प्रेशर से उन्होंने कुछ बड़ी अजीब बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की टांगें नहीं हैं, यह खड़ी नहीं हो सकती है, यह सरकार नाग-रिकों और उनकी सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकती है। मैं भी समझता हूं कि हमारी सरकार टांगों वाली सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी टाँगों वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी वह पार्टी है कि जिस तरह से बड़ का वृक्ष होता है, जिसकी जड़ जमीन के अन्दर होती है, उससे जो शाखायें निकलती हैं वे फिर नीचे की तरफ़ चली जाती हैं, और इस तरह से कई दरख्त बन जाते हैं। उसी तरह से हमारी पार्टी वह वृक्ष है जिसकी छाया के नीचे आप सब लोग रहे हैं। स्वतन्त्र पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोश-लिस्ट पार्टी या कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस वृक्ष की पैदावार नहीं है। कांग्रेस मां है, लेकिन मुझे अफसोस है कि फिर भी वह ऐसी बातें कहते हैं।

उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि स्वतन्त्र पार्टी उनको पसन्द नहीं करती है। मैं सम-झता हूं कि यह देश की खुशकिस्मती है कि श्री चव्हाण जैसे व्यक्ति इस वक्त देश के होम मिनिस्टर हैं। जिन हालात में उन्होंने देश को बचाया है, मैं समझता हूं कि इस के लिये उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। सारे देश को उन्होंने आग के शोलों से बचाया है, उन आग के शोलों से बचाया है, जिनको ये लोग फेंक रहे थे।

मैं श्री बलराज मधोक जी की भी बहुत इज्ज़त करता हूँ। वह मेरे दोस्त हैं,

मुझे दुख है कि आज मुझे उनकी एक बात का जवाब देना पड़ रहा है। उन्होंने अपनी स्पीच में सरकारी उद्योगों का जिक्र किया। हमने देश में बहुत से सरकारी उद्योग लगाये हैं, हैवी इन्जीनियरिंग, हिन्दुस्तान स्टील, वगैरह, इन सबको लगाने का मकसद क्या था ? आप इनकी प्रोजेक्ट रिपोर्टों को पढ़िये, इन उद्योगों के जरिये हमको उन मशीनों का निर्माण करना है जिनसे प्रोडक्शन हो सकती है यानी मशीनरी से मशीनरी पैदा करनी है। जाहिर है कि यह मुनाफ़े का काम नहीं है । आपने बोकारो का जिक्र किया, आप जरा बोकारो जाकर देखिये, ऐसा लगता है जैसे बोकारो हिन्दुस्तान का नया निर्माण कर रहा है। उसके मैनेजिंग डाइरेक्टर—शायद उनका नाम के० एम० जार्ज है—को मुबारकबाद दीजिए जो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक दिन रात काम कर रहे हैं, एक नये हिन्दोस्तान का निर्माण बोकारो में हो रहा है—इसकी ओर शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज जैसी फैक्टरी, इण्डियन आयल, शिपिंग कारपोरेशन, हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स, इण्डियन एयर लाइन्ज, एयर-इण्डिया, जैसे उद्योग इनकी नजरों में नहीं आते हैं।

उन्होंने एक बड़ी अनुचित बात कही है। प्रधान मंत्री जी की जेब में फॉरन-मिनिस्टर हैं या फॉरन-मिनिस्टर की जेब में प्रधान मंत्री हैं ··

श्री बलराज मधोक : लोग कहते हैं, मैंने नहीं कहा है।

श्री प्रेम चन्द वर्मा : एक पार्टी के नेता होने के नाते अगर इनके पास बोलने के लिए कोई मैटर नहीं है, तो बीच में क्यों आते हैं, कितना स्तर नीचा हो गया है, जाती बातें कही जाने लगी हैं। प्रधान मंत्री जी के बंगले का उन्होंने जिक्र किया । वह कोठी इतनी छोटी है कि विदेशों से जो लोग आते हैं,···(**व्यवधान**)···उन मिलने वालों के लिये बैठने तक की जगह वहां नहीं है। फिर यह मकान मौजूदा प्रधान मंत्री के लिए ही नहीं बन रहा है। बल्कि वह तो प्राइम मिनिस्टर हाउस बन रहा है । जो भी कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा वह उसमें रहेगा इसलिए मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाने के सम्बन्ध में किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होना चाहिए।··· (**व्यवधान**)···मैं समाप्त कर रहा हूँ।··· (**व्यवधान**)···इस सदन में एक बात और कही गई है जिससे मुझे बड़ा सदमा पहुँचता है ···(**व्यवधान**)···जो चीज हम सीखना चाहते हैं···(**व्यवधान**)···वह इसलिए सीखना चाहते हैं···(**व्यवधान**)···

SHRI S. K. SAMBANDHAN (Tiruttani): Mr. Chairman, I am happy to associate myself in paying our tributes and showing our gratitude to the President for the Address delivered to Members of Parliament but I have to couple this sense of gratitude with the sense of dissatisfaction and disappointment for views expressed and points made in his Address as also for important points left untouched by the President. I will refer to some of those points later.

The President has referred to integrated economic development of the country and expressed concern over parochial, regional, caste and communal movements. The Prime Minister too referred yesterday, when she was replying to the No-confidence Motion, to these things. I think, the Home Minister and other Members from that side also referred to these things when that motion was being discussed. I want to ask them only one question. Are the Prime Minister, her colleagues in the Cabinet and Members on the other side really sincere in expressing these things ? If they are really sincere and if they really want to put an end to these things, will they continue to act the way they have acted so far ? Let everyone of them consider it for himself and give

[Shri S. K. Sambandhan]
an answer for himself. It will only be in the negative.

Whenever we point out certain defects from this side and point out certain grave things like what has happened in Bombay and the atrocities done by the Shiv Sena, they simply refer back to the Member concerned and some of the parties on this side saying, "You too have done this or that." Like that they have referred to some incident in Tamil Nadu also. They have completely forgotten that they are the ruling party. They are there for the last so many years. They are the single largest party in the country holding responsibility at the Centre. I want to remind them of a Tamil as well as Sanskrit saying. In Tamil it is: *Arasan Evvazhi Avvazhi Kudigal* and it means that the way the king goes, the people in a country also go. The Sanskrit saying is: *Yatha raja tatha praja*. Being the premier political party of this country and a party that is running the administration for the last so many years from the date of independence, is it not the responsibility of this Government ? Should they not set up some good traditions so that other parties may follow ? If at all there is anything bad either in any of the Opposition parties or in any of the States run by the Opposition united parties, it is only because it is a reflection of what they had done in the past. So, let them think about this, correct themselves and set up good traditions so that our country progresses.

The President has appreciated the taking up of scientific agriculture by the farmers of the country. I do not want to refer to the hurdles, hardships and partiality experienced by the farmers because there will be no end to the hurdles and hardships experienced by the farmers throughout the country, from Himalayas to Cape Comorin. I can only say that the Government have forgotten that all their planning in agriculture will yield a certain percentage of fruits at least if only nature also cooperates. Otherwise, in case nature fails to cooperate, some alternatives, as far as possible, that could be implemented, that are practicable, should be planned and implemented. One such thing is the utilisation of our river waters of the country. We have big rivers running in the north, medium rivers in the middle of the country and small rivers in the south. Many people have suggested the linking of these rivers. If the Government were sincere all along, they would have linked all the rivers of the country within these 21 years since we won Independence. They have not done it. They are only saying that we will become self-sufficient after 2 years. Every two years, they talk like that.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): From 1960, they are building the buffer stock.

SHRI S. K. SAMBANDHAN: Almost every alternate year there are floods in some parts of the country and drought in other parts of the country. If they were really sincere they would have done something. Is it not their primary duty to fulfil targets as far as agriculture is concerned ? In order to fulfil targets, the main thing is availability of water facilities for irrigation. Why have they not done it ? Are they going to do it ? They have not taken a decision even about Narmada, Godavari and Krishna. That shows they are not sincere in the welfare of the country. There is indecision on the part of the Government in regard to this. They are not at all sincere in what they say.

Yesterday, Prof, Ranga also referred to disparity and differential treatments leading to so many disturbances in the country. One such disturbance has occurred in Telengana. The Government should take care to see that no disparity or differential treatment is meted out to any section of the population or any part of the country. If we take up the agricultural development, we can easily point out what disparities and prejudicial or differential treatment has been shown in the past.

Then, my hon. friend, Shri Prem Chand Varma also spoke at length about big projects and the creation of new India. But he has forgotten the amount of money that is being spent and criminally wasted

to the tune of hundreds of crores. The total outlay amounts to more than 1000 crores. There are so many steel plants in the north. The south has been asking for steel plants. Tamil Nadu, particularly, has been asking for a steel plant for the last so many years, not only now after the D. M. K. Government has come to power, even long before that. Mysore and Andhra have also been demanding a steel plant. In all these places, a steel plant would cost about Rs. 100 to 200 crores. If three steel plants are located in these three States, it will not come to the cost at which Bokaro plant is being put up. But they are not sincere in locating steel plants in the south. They have not realised that these three plants will provide employment, twice or thrice the number of people that Bokaro plant can provide. We are facing the problem of unemployment in every State. Our population is alarmingly growing. At this juncture, is it not the duty of the Central Government to think of that problem also ? They are not doing that. If they have not done it, is it not our duty to accuse them or blame them.

As far as the Tamil Nadu steel plant is concerned, even when the Congress Government was there, Mr. Venkataraman who is now the Member of the Planning Commission was the Industries Minister of Madras and he went to Japan and asked the Japanese experts to come to Madras and explore the possibilities of setting up a steel plant there. The Japanese experts worked out the details and gave the economics of it also. They said that it is economically feasible and it will work profitably also. There was some correspondence with the Central Government when Mr. Venkataraman was the Industries Minister of Madras.

The Japanese also came forward for collaboration. In spite of that, the Central Government did not agree to that. Even today they are not agreeing. If such a differential treatment and partiality goes on, do you think that everybody will keep silent for long ? Is it democracy then ? Do the Government want such a democracy, I want to ask. If it is really a democracy, then they have to concede in the Fourth Five-Year Plan one steel plant at Salem.

So also, there are disparities and partialities in the case of railway lines. We have been asking for doubling of the railway line from Madras to Villupuram which has been electrified recently. Without doubling the benefit of electrification is not at all felt. The trains have to stop at each and every station, even though they are not scheduled to stop, for crossing purposes. If you see the amount spent in the North and the amount spent in the South, then that will show the disparity and partiality of the Central Government towards the Southern States.

About two years ago, at the beginning of this Lok Sabha, they said that the proposal for electrification of the line from Madras to Arkonam, which is a distance of only 40 miles, would be taken up, but no proposal has been made so far; not even investigation has been done. I do not know why. If such a partiality is shown, I do not know what will be the position of the people of Tamil Nadu. I would request the Government to take up at least now the electrification of the line from Madras Central to Arkonam.

Then I come to the question of language. Yesterday, the eldest Member of this House, Shri Govind Das, said that every one should sacrifice to a certain extent. He wanted sacrifice on our part. I would like to ask him and the other fanatics of Hindi whether it is not their duty to show some sacrifice. The official language, which is already in existence and with which we are more conversant, is still being used in every corner of the country. Why should it be replaced unnecessarily ? That is a common language, the most convenient language, now for the whole world. In spite of that, large amounts are being spent in the introduction of Hindi. For instance, we get so much of papers in Hindi and we have to waste our precious time in sorting out the papers. It is a criminal waste. If with the same print and ink, text-books could be printed and distributed to the poor students from the primary stage to

[Shri S. K. Sambandhan]

the university stage, it would be very helpful. So much of money is being criminally wasted on Hindi papers and in the introduction of Hindi. Hindi is being forced through the backdoor method on the Central Government employees. I would warn the Government against the consequences if they continued to do it.

The Prime Minister and the others speak of integration and of Centre-State relationship. In a democracy, particularly of the type that we have, only the States can deliver the goods to the common man and to the public at large. So, socialism or nationalism or integration should be correctly understood by the party in power. Only the States can deliver the goods to the public and, therefore, the States should be given more funds and more powers also. It is of no use wasting the money at the Centre. I would, therefore, request the Government to have a rethinking on all these aspects and do the right thing.

Then, I would like to point out the disparity shown by the Central Government in regard to development of handloom industry. The handloom industry is one of the biggest cottage industries in the country, next to agriculture, and provides employment for lakhs and lakhs of persons.

Lakhs and lakhs of persons along with their families are engaged in the handloom industry. The ruling party speaks of Gandhiji and it is celebrating the Gandhi Centenary year. Gandhiji was all for cottage industries including the khadi industry. Khadi is no different from handlooms. In the khadi industry they use handspun yarn. But the number of people engaged in the khadi industry is absolutely small compared to the number of people depending on the handloom industry. A few lakhs and lakhs of people are either unemployed or underemployed in the handloom industry due to the negligence and careless administration of even the meagre funds made available to the handloom industry. The figures will show that for the few lakhs of people depending on cottage industries, in the Third Five Year Plan Government spent Rs. 94 lakhs, whereas on the handloom industry on which more than 10 to 15 million people depend, they had spent throughout the Third Five Year Plan only about Rs. 24.76 lakhs. Is this reasonable ? I would ask Government to apply their mind to this kind of disparity. Whatever affection they may have for the khadi industry, yet, there should not be so much of disparity. In the name of Gandhiji, I would request them when they are celebrating the Gandhi Centenary Year to show some reasonable attitude towards the handloom industry.

SHRIMATI SUDHA V. REDDY (Madhugiri) : I have great pleasure in endorsing the Motion of Thanks on the President's Address.

The President is to us the palladium of all civil rights and liberty, which have been amply demonstrated in the recent mid-term elections that we have had in several major States. In this connection, I would like to recall the words of Ernest Barker; in his *Principles of Social and Political Theory* he has made some very interesting observations about the rights and functions of the State. He has said :

> "It can declare and guarantee the rights and duties of religious societies but it cannot itself be a religious society. It can declare and guarantee the rights and duties of authors, teachers and all other persons engaged in the creation and transmission of culture; it cannot, however, itself be the creator and inculcator of culture. It can declare and guarantee the rights and duties of all agents engaged in social and economic production ; indeed, it can even become itself an agent in an area if a due guarantee of the rights of the labouring classes and of their employers cannot otherwise be provided ; but it offends against its own nature and it encroaches on its own primary legal function if it loads itself with any large burden of direct economic or social activities. It is a supervisor of activity and not a generator. It is the author of a framework of rights and duties but it cannot be the whole framework of rights and duties by itself."

My point of view must necessarily be that of a social worker. Somebody said of a social worker that she or he must have the strength of a horse, the hide of an elephant, the eye of a hawk, the wisdom of a serpent and the harmlessness of a dove.

But today I see a very amusing spectacle which seems a little more diverse than the picture of the social worker that I gave you—this we see in West Bengal. It seems to me that the picture of this miniature zoo presents the eye of a falcon looking out for creating trouble, the hide of a buffalo, the hissing of a serpent, the beak of an eagle and the trunk of an elephant trying to throw water on problems temporarily, only to be sorted out again by some other party. With the conglomeration of faculties like this, Communists, Left, Right and Centre, the Bangla Congress, the SSP and the S. U. C. it presents a spectacle of an Unlike-minded Uneasy Front. "Uneasy," they say, "lies the head that wears the crown." But this animal has as many heads as Ravana, and I hope that all the heads will lie easy and deliver a good administration to the State that it governs.

15 hrs.

We are very thankful for secularism, irrespective of what our friend Shri Bal Raj Madhok said here this afternoon. But at the same time, secularism is today increasingly becoming significant of irreligiousness. After all, religion, etymologically, means nothing else but to bind. And irrespective of what religion it be, be it the religion of the Self or any other, I hope that this spirit of religiousness will be exercised and taught more and more especially to the younger generation.

On the motion of no-confidence, many of the Members opposite spoke eloquently and at very great length averring that all that they said was for the benefit of posterity. In fact, at one time I was afraid that if they did not hurry up, posterity would be here to hear them. It is this posterity that has to be looked after and nurtured and nourished.

May I suggest that there are certain sections, weaker sections of the public, other than those mentioned in the Constitution ? And there I may include women and children. I think the Commission on Backward Classes said that women would be included amongst the backward classes. Why they said it, I do not know ! May I suggest that this country may go increasingly under the administration of housewives ? It will do the country good. I think men have had many trials and errors at making messes ; so, why not the women ? The time has come when women must be taught better methods of agriculture, because after all, it is the women who do 60 per cent of the agricultural operations, right from the seeding, harvesting, winnowing, storing etc. up to the cooking of the grain in a palatable form for their lords and masters who could sit up and criticise later on. May I also suggest that greater care must be taken in nourishing backward areas which have remained backward despite all the crores that have been spent on them. It is likely that every time it was a question of putting out temporary palliatives which were absolutely temporary in their effect. I think the time has now come when schemes for the backward areas must be put on a war footing, when money must be found for these ameliorative schemes, irrespective of whether moneys are found for other large prestige projects. After all, one must remember—I think the Kumbhakarna of our Government has woken up to realise—that "अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्" ।

It is not steel alone that is Brahma. Man cannot eat steel. One must remember that if these areas remain backward for any length of time, the flames of discontent can be fanned by many interested people, irrespective of the party they come from and these gullible victims can be taken advantage of and nobody can blame them if they go astray.

After all, one must remember the old saying: 'न नरो नरस्य दास : दासस्व अर्थस्य' 'No man is any other man's servant; man is only a servant of *artha*, that is money.

Some spoke of the Congress Party being servile to merchant princes; others spoke of some other parties being servile to Maharajas and Maharanis; some others spoke of money orders coming from China. But

[Shrimati Sudha V. Reddy]

ultimately, it filters down to one thing, that money has a very great place in the life of man; everyone must have a minimum of money, and towards this end economic production has to be stepped up and geared at every stage.

Regarding agriculture, may I mention some of the problems which confront the countryside ? Especially in Mysore State, many of the tanks are hundreds of years old; they have neither been repaired, nor desilted from the bank. They have outlived the optimum purpose for which they were dug, and the country, lost in these grandiose projects, is just now waking up to minor irrigation on an intensive scale. I hope minor irrigation and soil conservation will receive enhanced priority in the years to come.

Another programme which must be undertaken from my point of view is, apart from slum clearance, more ameliorative schemes for slum areas. Many governments have tried to clear slums and have failed, but surely ameliorative programmes can be undertaken. I may even go to the extent of saying that the birthplace of senas is usually in slum areas. Living with no privacy, with just a couple of inches to move in, living in such irritating, sardine-packed proximity to one another, creates a psychological tension which can only break out in violence. We have seen plenty of demonstrations of these attitudes, these flaming emotions, whether they be located in Bombay or Calcutta or one other place. I think Government must undertake programmes of high priority in these areas.

One other plea which I would make is this. While I have no doubt at all that decisions are taken in good time and for good reasons, I would like them to be expedited. Whether they relate to awards or to industrial licences or to riparian disputes or other things, delays can be absolutely frustrating, and there are experiences which defeat any argument. I would, therefore, quote one of Tolstoy's sayings, 'Too late to go here, too late to get there, too late to get anywhere.'

Let us depart from this and see that decisions are taken keeping in mind the old adage: justice delayed is justice denied. In the same plea I may include the Mahajan's award which is the fourth award with regard to Mysore's boundaries—it should be given effect to.

While education has a high priority, we seem to have forgotten that education really means in the Oxford Dictionary the training of character. What we have in mind by the word education is a sort of "*udhara nimittha*", to fill one's stomach. That is characteristic of a poor nation and nobody can be blamed for this attitude. Let us then be practical and link up our requirements of university education with our employment potential; let us not create an ocean of disturbance in the minds of the educated young who have no jobs to find. I remember that many years ago the Ramaswamy Mudaliar Committee went into this matter and suggested that the matriculation standard should be enough for most white collar jobs. I wish we kept to that because, as that famous educationist Oliver Reddicks noted, even very affluent countries have not tried to make university education universal; but here, we, a poor country, are trying to do that. Insistence on a good standard in matriculation examination should more than suffice for ordinary life.

15-12 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

My suggestion as a housewife is that our industries should be more consumer oriented and not sentiment or ideology oriented. We see that the HMT watch factory has made a success.

It is by this means that Japan has progressed despite all the devastations that overtook it during the Second World War. What the Japanese can achieve, we can, with a little more hard work. I also feel that the expansion of the various industrial units, especially the State-owned ones should be located in areas where the parent factories are located because there is a duplication of administrative buildings, staff and housing colonies and so much of capital expenditure becomes unfruitful.

We have learnt to speak only in terms of crores. Let us humble ourselves in figures. I know sometimes it incurs the

wrath of demographers when figures shrink. But let us assume some amount of humility in figures. Why cannot we take pride in smaller projects, not in the optimum but in the minimum because those are the ones which will really, in the long run, progress and become viably productive. Let us see that the taxes are well utilised on the smaller projects rather than on white elephants which cannot be maintained by any State however affluent it may be.

May I also make one passing remark ? Mr. Dandeker mentioned the wealth-tax, gift-tax, expenditure tax, this tax and that tax ! I am wondering whether his party can say a "Happy New Year" to this country with no taxes at all; if it does, we would be very glad to vote them in.

May I also plead for the Rajasthan Canal and also pay a tribute to the great lady who made such a verbal effort regarding the bringing in of this canal, at the same time, keeping her area so poor that the Congress Government could step in and look after the construction of that canal in the second half of the 20th century.

Let us remember that we are, altogether in an infant democracy. We have slipped up on many counts, since we have been learning by the method of trial and error, but I have no doubt that whatever party affiliations we have, we will all contribute to a healthy evolution of this great country of ours.

Thank you.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगूसराय) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण को हमने बहुत आदर के साथ सुना और बहुत ही आदर के साथ पढ़ा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभिभाषण खोखला है। उस अभिभाषण में आत्मा नहीं, केवल आडम्बर है। राष्ट्रीय वास्तविकता की जो पकड़ होनी चाहिये उसमें उसकी जगह केवल आत्म-तुष्टि का सहारा है, सरकार की नीतियों और सरकार के उद्देश्यों को रखने की जो कोशिश होनी चाहिये उसकी जगह केवल सदिच्छा की अभिव्यक्ति है आत्म-तुष्टि, अकर्मण्यता और निष्क्रियता पैदा करती है और यही कारण है कि सरकार को अकर्मण्यता और निष्क्रियता का शिकार होना पड़ा। सदिच्छाओं से पटा हुआ रास्ता अक्सर नर्क को ले जाता है और आज हमारा देश उसी अधोगति की ओर जा रहा है। आत्म-तुष्टि की जो भावना है वह अभिभाषण के अंग्रेजी संस्करण से बहुत अधिक बढ़-चढ़कर हिन्दी संस्करण में है। आप पूछ सकते हैं कि यह कैसे सम्भव है। एक ही अभिभाषण के दो संस्करण और दोनों में दो तरह के मूल्यांकन। हमको भी आश्चर्य हुआ। जब हमने राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण सुना और पढ़ा तो एक ओर हमें यह खुशी हुई कि कुछ सरल हिन्दी लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी ओर जब हमने उसको पढ़ा तो देखा कि मूल्यांकन भी दो तरह के हैं, अँग्रेजी और हिन्दी में अलग-अलग। अँग्रेजी अभिभाषण में नुकता नं० 18 में कहा गया है कि :

> "The burden of servicing the external debt is mounting and amounts to 514 million dollars this year."

एक्स्टर्नल एड की सर्विसिंग में हमें इस साल 514 मिलियन डालर देने पड़ेंगे। लेकिन हिन्दी संस्करण क्या बोलता है ?

> "विदेशी सहायता के विषय में बड़ी अनिश्चितता आ गई है। विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और इस वर्ष 51 करोड़ 40 लाख डालर हो गया है।"

जब वहां पर एक्स्टर्नल एड सर्विसिंग है तो यहां पर पूरा कर्ज है।

मेरी समझ में नहीं आता कि मैं हिन्दी अभिभाषण के मूल्यांकन के आधार पर अपना भाषण करूं या अंग्रेजी के।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : पहले हिन्दी में ही भाषण हुआ था।

MR. DEPUTY-SPEAKER : It might be a printing slip. I have followed it.

श्री मधु लिमये : प्रिंटिंग की नहीं है।

श्री योगेन्द्र शर्मा : अर्थ का भेद है।

राष्ट्रपति ने अपने अंग्रेजी भाषण में कहा कि हर एक साल विदेशी कर्ज और सूद की अदायगी में 385 करोड़ 50 लाख रुपये देने पड़ेंगे। हिन्दी में कहा गया है कि इतना ही विदेशी कर्ज है जबकि विदेशी कर्ज की मात्रा हमारे ऊपर करीब 5800 करोड़ की है।

यह सारा विदेशी कर्ज कांग्रेस सरकार ने पिछले बीस सालों के दौरान देश के माथे पर लाद दिया है और इसका नतीजा यह है कि हमारे देश को करीब चार सौ करोड़ रुपया सिर्फ सूद की अदायगी में देना पड़ता है। उसके बदले में हमने देश में क्या किया है ? इस विदेशी कर्जे को लेकर हमने देश में आर्थिक प्रगति के कौन से काम किये हैं ?

अभिभाषण में कहा गया है कि आर्थिक संकट से हम निकल रहे हैं। काश हम निकलते होते। लेकिन वास्तविकता दूसरी है। वास्तविकता यह है कि देश अभी भी आर्थिक संकट के भंवर में फंसा हुआ है। खेती की पैदावार की बात कही गई है। यह कहा गया है कि उसमें मोड़ आ गया है। लेकिन इसी अभिभाषण में यह भी कबूल किया गया है कि 1967-68 में जो पैदावार हुई थी वही पैदावार 1968-69 में भी होने जा रही है। यह चीज तो पैदावार में मोड़ की सूचक नहीं है, यह तो पैदावार के ठहराव की सूचक है। पिछले साल जितनी पैदावार हुई उतनी ही पैदावार अगले साल भी होने जा रही है, यह तो प्रगति की सूचक नहीं है, ठहराव की ही सूचक है। आपने एक विशेष साल का मुकाबला इस साल की पैदावार से किया है और कहा है कि इतनी प्रगति हुई है लेकिन वह सूखे और अकाल का साल था। मैं आपका ध्यान दिवंगत प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के उस भाषण की ओर ले जाना चाहता हूं जो उन्होंने 1955 और 1956 में दिया था, जिस साल कि मौसम की दया से हमारे देश में बड़ी अच्छी फसल हुई थी। उन्होंने कहा था कि दो साल में हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेंगे। लेकिन आज उस बात को कहे हुए दस साल से भी अधिक हो गए हैं, हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। हमारी निर्भरता अन्न के मामले में दस साल पहले के मुकाबले में विदेशों पर आज और भी ज्यादा होगई है। मैं नहीं समझता हूं कि सरकारी दल की ओर से कोई भी सदस्य इस तथ्य से इन्कार कर सकता है। आज से दस साल पहले हम विदेशों से जितना अनाज मंगाते थे उससे ज्यादा अनाज आज हम मंगाते हैं। क्या यह प्रगति की द्योतक है ? यह तो अधोगति की ही द्योतक है। यह तब है जबकि हम अपने देश के माथे पर 5800 करोड़ रुपये का कर्ज लाद चुके हैं और ऐसा मालूम होता है कि हमने अपने देश के भविष्य को गिरवी रख दिया है।

औद्योगिक उन्नति की बात भी कही गई है। हकीकत क्या है ? हकीकत यह है कि जो उद्योग धन्धे खड़े किये गये हैं उनकी जो क्षमता है वह देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, देश के विकास की आवश्यकताओं का विचार करते हुए, कम है। लेकिन फिर एक और दुर्भाग्य की बात भी है। जो क्षमता है भी उसका भी पूरे तौर पर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमको दर्द होता है जब हम देखते हैं कि हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन की जिस क्षमता का हमने हजारों हजार करोड़ रुपया लगा कर निर्माण किया है, उसके बीस पच्चीस प्रतिशत का ही हम आज इस्तेमाल कर पा रहे हैं।

कीमतों में स्थिरता की बात भी कही गई है। लेकिन इसके साथ साथ इसी अभिभाषण में यह भी स्वीकार किया गया है कि यह समस्या खड़ी हो गई है कि किसान को

खेती की पैदावार की मुनासिब कीमत मिले, इसके बारे में भी हमको सोचना होगा। एक तरफ आप अभिभाषण में इस बात को स्वीकार करते हैं कि आज किसान के लिए उचित कीमत एक चिन्ता का विषय हो गया है और दूसरी तरफ आप कीमतों में स्थिरता की बात करते हैं, ये दोनों बातें एक साथ कैसे चल सकती हैं और कैसे सही हो सकती हैं। हकीकत यह है कि औद्योगिक माल की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं और इजारेदारों के चंगुल में जो हमारी अनाज की मंडियां फंसी हुई हैं उनकी वजह से आज किसान के सामने एक भयंकर खतरा पैदा हो गया है उसको मुनासिब कीमत मिलेगी भी या नहीं। इसलिए कीमतों में कमोवेशी स्थिरता की बात करना गलत है। हमारे सामने यह समस्या बरकरार है कि कैसे हम कीमतों पर काबू पायें।

आर्थिक स्थिति के सुधार की बात भी कही गई है। ऐसा मालूम होता है कि सरकारी दल के सामने इस देश के कुछ मुट्ठी भर लोग ही हैं, आम जनता नहीं है। यदि आम जनता होती तो इस बात को समझने में उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिये थी कि इस देश में जो तथाकथित कमजोर श्रेणी के लोग हैं, उनकी तरफ पहले ध्यान किया जाना चाहिये। अभी अभी कांग्रेसी सदस्य बोली हैं। उनसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि औरतों की गणना भी कमजोर श्रेणी में होनी चाहिये। कमजोर श्रेणियों में और कौन कौन आते हैं? हरिजन आते हैं, आदिवासी आते हैं, मजदूर आते हैं, खेतिहर मजदूर आते हैं, गरीब किसान आते हैं। ये सरकार के सामने होते तो यह सोचती कि 5800 करोड़ रुपये का कर्ज का बोझा कंधे पर उठा कर भी हम देश में इन गरीब लोगों के लिए क्या वाकई में कुछ कर पाये हैं? आप देखें कि 34 परसेंट से भी अधिक लोग देहातों में ऐसे हैं जो सिर्फ पन्द्रह रुपये महीना खर्च कर सकते हैं और शहरों में करीब 24 रुपये महीना। दूसरी ओर हालत यह है कि दो साल के भीतर हमारे देश के एक बड़े इजारेदार बिरला साहब ने अपनी पूंजी में करीब सवा सौ करोड़ रुपये की वृद्धि की है। एक दूसरा इजारेदार घराना उससे प्रतियोगिता कर रहा है और कहता है कि मैं खाद का कारखाना खोल कर इस पूंजी से भी आगे बढ़ जाऊंगा। इजारेदारों की पूंजी बढ़ती जा रही है, उनके मुनाफे बढ़ते जा रहे हैं। जो गरीब हैं वे मर रहे हैं। महीने में पन्द्रह रुपये भी खर्च करने की क्षमता उनमें नहीं है। आप आर्थिक प्रगति की बात करते हैं। आर्थिक प्रगति से मतलब अगर टाटा और बिरला की आर्थिक प्रगति से है तो हमको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप देश की अर्थिक प्रगति की बात करते हैं तो इस देश में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं, हरिजन भी हैं, उनकी हालत को आपको पहले सुधारना चाहिए। उनकी आज हालत यह है कि उनके लिए जिन्दा रहना भी इंसानों की तरह असम्भव हो गया है।

पिछले साल सरकारी कर्मचारियों ने नीड बेस्ड मिनिमम वेज की मांग उठाई थी और यहां तक कहा था कि यदि आप उनकी इस मांग की पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस मांग को पंचों के हवाले कर दें। इससे भी आपने इन्कार किया और इन्कार ही नहीं किया बल्कि लाठियों और गोलियों का उनको शिकार बनाया। न केवल लाठियों और गोलियों का शिकार बनाया बल्कि आज करीब दस हजार कर्मचारियों को आपने दण्डित कर रखा है शत्रुतापूर्ण व्यवहार करके। पता नहीं आप उनको कहां पहुंचाना चाहते हैं। आप प्रगति और तरक्की की बात करते हैं। क्या प्रगति और तरक्की किसानों और मजदूरों की इस सरकार ने की है या टाटा और बिरला जैसे लोगों की की है। यदि आप सभी को भारत माता की संतान

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

समझते हैं तो सबकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये था और विशेष कर इन गिरे हुए लोगों की तरफ देना चाहिये था लेकिन आपने कुछ मुट्ठी भर इजारेदारों की तरक्की की बात ही सोची है। तरक्की से यदि आपका मतलब इजारेदार लोगों की तरक्की से है, कुछ राजे और रानियों से है तो फिर हमको कुछ नहीं कहना है। तब हमको आपके साथ इस बात पर लड़ना होगा कि तुम्हारा देश अलग है और हमारा देश अलग है, हमारा देश भारत की जनता है, तुम्हारा देश भारत के राजे और रानियां, और टाटा और बिरला है। भारत की एकता यदि कायम रखनी है तो हमारा अनुरोध है कि जो दृष्टिकोण आपने अपना रखा है, इसको आप त्यागें। समता का दृष्टिकोण आपको अपनाना होगा। वर्ना विषमता की खाई बढ़ेगी और वह बढ़ती भी जा रही है। यदि इस खाई को पाटने की कोशिश नहीं की गई तो यह खाई और भी बढ़ती जाएगी और देश की एकता खतरे में पड़ जाएगी और अगर यह एकता भंग हुई तो शासक दल होने के नाते इसकी तमाम जिम्मेदारी आप पर होगी।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इस बढ़ती हुई आर्थिक विषमता का और इन सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया है, कोई उल्लेख नहीं है। इसका अर्थ क्या यह लगाया जाए कि आपके सामने इस देश की मेहनतकश जनता नहीं है, देश के मुट्ठी भर इजारेदार और शोषक लोग ही हैं ? चूंकि आपके सामने यही लोग हैं इस वास्ते आज देश की आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाती है। इसी कारण से आज देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है और आपको अपने कंधों पर 5800 करोड़ रुपये का कर्जा लादना पड़ गया है जिसका चार सौ करोड़ रुपया सालाना आप सूद दे रहे हैं।

आपकी योजना आज ठप्प है। आप कहते हैं कि ठप्प नहीं है, योजना अप्रैल से लागू होगी। कौनसी योजना लागू होगी ? आज से दस पन्द्रह साल पहले आपने एक सीमित योजना बनाई थी। आज आप में यह सामर्थ्य नहीं रह गई है कि उस योजना को भी आप चला सकें। तीन साल छुट्टी देने के बाद आप जो योजना लागू करने की बात कर रहे हैं, वह योजना नहीं है, वह तो केवलमात्र योजना का एक आवरण है। उसकी आत्मा को आपने खत्म कर दिया है। वह तो एक नेशनल प्लान जिसको कहा जाता है वह होगा। योजनाबद्ध विकास करने की बात आपने खत्म कर दी है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं यही उसका हश्र होगा।

इसका कारण यह है कि देश के भाग्य और भविष्य को इजारेदारों की मुट्ठी में देकर देश का योजनाबद्ध विकास नहीं किया जा सकता है। आज योजना के ठप्प होने का प्रधान कारण यह कि इस सरकार ने देश के भाग्य और भविष्य को मुट्ठीभर देशी और विदेशी इजारेदारों के हवाले कर दिया है।

इस सरकार की तरफ से स्वदेशी की बात कही गई है—गांधी जन्म शताब्दी के साल में स्वदेशी की बात कही गई है—उस स्वदेशी की, जिसका झंडा महात्मा गांधी ने फहराया था। लेकिन स्वदेशी के प्रोत्साहन के लिए यह सरकार क्या कर रही है ? अभी कुछ दिनों पहले हमारे उप-प्रधान मंत्री और उद्योगपतियों के एक नेता, श्री एल० एन० बिड़ला, ने अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी विनियोग पर हुई एक विचार गोष्ठी में यह घोषणा की कि राष्ट्रीय उद्योगों में विदेशी खानगी पूंजी को उदारतापूर्वक आमंत्रित करना पड़ेगा। यह सरकार 5800 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर भी संतुष्ट नहीं है। वह हिन्दुस्तान में ऐसे विदेशी मालों का आयात करके भी संतुष्ट नहीं है, जिसको हम अपनी पूंजी, अपने

परिश्रम और टेकनीक से यहां ही पैदा कर सकते हैं। वह विदेशी पूंजी को यहां पर आमंत्रित करके इस देश के गले को नागपाश में डालना चाहती है। यह सरकार आज देश के पूरे अर्थ-तंत्र को विदेशियों के हवाले कर रही है। कम-से-कम गांधी-जन्म-शताब्दी के साल में तो इस धारा को पलटना चाहिए, इस को बन्द करना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी इस बात का आभास नहीं मिलता है।

विदेशों से इतना बड़ा कर्ज लेकर हमारे देश की बेकारी की समस्या हल नहीं हो पाई है। आज हालत यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है। 1961 में ग्रामीण क्षेत्र में 80 लाख बेकार थे, जो कि आज बढ़कर डेढ़ करोड़ हो गये हैं। अर्द्ध-बेकार और मौसमी बेकार इनके अलावा हैं। शहरी क्षेत्र में 1950-51 में निबन्धित बेकारों की संख्या 3,31,000 थी, जो बढ़कर 1967-68 में 27,40,000 हो गई है। क्या यह हमारी आर्थिक प्रगति की निशानी है? क्या यह हमारे आर्थिक संकट की समाप्ति का परिचायक है?

हमारे देश के नौजवान बड़ी उम्मीद, उद्गार और आशा के साथ स्कूलों और कालेजों में पढ़ते हैं कि हम देश के निर्माता बनेंगे, हम देश का निर्माण करेंगे, लेकिन आज वे बेकारी के मुंह में जा रहे हैं। जब वे आन्दोलन करते हैं, तो हम उनको अनुशासन सिखाते हैं। अगर उनको अनुशासन सिखाना हो, तो पहले उन्हें रोजगार और काम देना होगा, उनकी बेकारी की समस्या को हल करना होगा। इसके बिना अनुशासन की बात उनके कानों में नहीं उतरेगी। आज बेकारों की संख्या दिनों-दिन बढ़ रही है। उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, जब इस सरकार ने योजना को खत्म कर दिया है, विकास-कार्यों को ठप्प कर दिया है?

आज देहातों में बेकारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बड़े-बड़े हजारपतियों और लखपतियों ने गरीब किसानों की जमीनों को खरीद-खरीदकर हड़प लिया है, जिससे बेज़मीन और बेकार हो गये हैं। इस सरकार ने कहा था कि वह भूमि-सुधार करेगी, हद-बन्दी करेगी। उसने यह भी कहा था कि वह आमदनी की हद-बन्दी करेगी। लेकिन इस अभिभाषण में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। मालूम होता है कि सरकार ने उन नीतियों को छोड़ दिया है। जितने ही बड़े हजारीमल होंगे, उतना ही वे लूट-खसूट करके ज़मीन का केन्द्रीयकरण करेंगे। इस समस्या का एक-मात्र हल यह है कि सरकार इस लूट को बन्द करे, इन बेदखलियों को बन्द करे, उसने भूमि-सुधारों की जो घोषणा की थी, उसको कार्यान्वित करे।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member should try to conclude in the couple of minutes. He has taken 20 minutes. There is not much time left for his group.

SHRI YOGENDRA SHARMA : I will need another five minutes. I should conclude on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right; he may resume his speech on Monday. There is very little time left for him.

15.36 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS FORTY-THIRD REPORT

SHRI BHALJIBHAI PARMAR (Dohad) : Sir, I beg to move :

> "That this House do agree with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 20th February, 1968."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

> "That this House agree with the Forty-third Report of the Committee on Private Members' Bills and